हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल आरम्भ

तारांकित प्रश्न

18.03.2016/1100/TCV/AG/1

प्रश्न संख्याः 2978

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले में आपका धन्यवाद करता हूं कि इस विधान सभा में मुझे 8 साल हो गये हैं और 8 साल में मेरा पहली बार प्रश्न लगा है जो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें इन्होंने बताया कि इस सिविल अस्पताल को बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के नाम कुल कितनी भूमि है? क्या यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा भी कर रखा है? आपने कहा कि भवन के लिए 160.83 लाख रूपया आपने दे दिया है तो क्या जहां आप भवन निर्माण का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने जा रहे है वर्तमान में वहां पर भूमि उपलब्ध है?

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत तौर पर जब सिविल हॉस्पिटल, बंजार गया था और माननीय स्थानीय विधायक और वर्तमान मंत्री जिनके चुनाव क्षेत्र में यह सिविल हॉस्पिटल है, मैंने विस्तृत तौर पर पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां कुछ खोखे टाईप पुराने डिलैपिडेटिड कमान बने हुए थे। मेरे साथ वहां के एस0डी0एम0, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग और उसके अलावा और अधिकारी भी साथ थे। मैंने उनको उसी वक्त हिदायत दी कि इन डिलैपिडेटिड मकानों के डिसमैंटल की प्रोसैस जारी करें और वह प्रोसैस जारी हो चुका है। उसके बाद मैंने कहा इसका डिटेल्ड एस्टीमेट बनाकर हिमाचल सरकार को प्रशासनिक अनुमति के लिए भेजें। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने बहुत हायर साईड में मु0 15 करोड़ 58 लाख रूपये का इसका एस्टीमेट भेजा है फिर भी हमने उसको प्रशासनिक अनुमति दे दी है और मेरा पूरा विश्वास है कि लोक निर्माण विभाग अब जल्दी से इस भवन को तैयार करने के लिए कदम उठाएगा।

अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी, आप और क्या पूछना चाहते है?

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

18.03.2016/1105/RKS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2978...क्रमागत

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर 6 छोटे-छोटे भवन हैं, जो खंडहरनुमा हो चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये भवन कब तक डिस्मेंटल होंगे? लोक निर्माण विभाग ने इन भवनों को डिस्मेंटल करने के लिए क्या पग उठाए? क्या टेंडर इत्यादि करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है? मेरा प्रश्न यह भी है कि अगर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की भूमि में कब्जा कर रखा है तो क्या स्वास्थ्य विभाग उसकी डिमार्केशन करवा कर उस जमीन को अपने कब्जे में लेगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब मैं वहां मौके पर गया तो स्थानीय प्रतिनिधि भी मेरे साथ थे। एस.डी.एम. और तहसीलदार भी मेरे साथ थे। मैंने उसी वक्त उनको हिदायत दी की सारे स्वास्थ्य विभाग के जमीन की डिमार्केशन की जाए और किसी ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर नज़ायज तौर पर कब्जा कर रखा है तो उसको उठाने की कार्रवाई की जाए। जहां तक खंडहर भवनों को डिस्मेंटल करने की बात है उसके लिए प्रक्रिया होती है। उसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसका चेयमैन एस.डी.एम. होता है और लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी साथ जाते हैं। वे लोग इस बारे में सर्टिफिकेट देते हैं तब केस आगे एप्रूवल के लिए भेजा जाता है। हमारी कोशिश होगी कि पी.डब्ल्यू .डी. विभाग जल्दी से जल्दी टेंडर प्रकिया शुरू करें ताकि बंजार में एक भव्य भवन का निर्माण किया जा सके।

18.03.2016/1105/RKS/DC/2

प्रश्न संख्याः 2979

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो आई.पी.एच. विभाग में फिल्ड स्टाफ है, उसमें हजारों पद खाली पड़े हुए हैं।

कुछ पदों को डैड घोषित कर दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले इस समर में पेयजल व्यवस्था, सारा प्रशासनिक ढांचा चरमरा जाएगा। हालांकि इस बारे में जब डिमांडज पर चर्चा होगी तो बात की जाएगी। लेकिन अपने मूल प्रश्न कि ओर ध्यान दिलाते हुए मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सूचना आपने रखी है उसमें प्रदेश में पेयजल की कुल 41 प्रयोगशालाएं हैं। 41 में से 14 प्रयोगशालाएं विभाग चला रहा है और 27 निजी क्षेत्र को दे दी गई है। इनमें 8 पद रिक्त बताए जाते हैं। यह पद कब से खाली है और क्या कारण है कि ये पद आज दिन तक नहीं भरे गए? जो 14 प्रयोगशालाएं विभाग चला रहा है और जो 27 प्रयोगशालाएं निजी क्षेत्र को दे दी गई है, इसका निर्णय किस स्तर पर हुआ है? इन प्रयोगशालाओं में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर आपके पास इसका विस्तृत जवाब नहीं है तो आप इसकी सूचना बाद में भी दे सकते हैं। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः श्री महेश्वर सिंह जी जो आपने प्रश्न संख्याः 2979 में अनुपूरक प्रश्न किया है उसके बारे में, मैं आपको बताना चाहती हूं

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

18.03.2016/1110/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 2979 ...जारी

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ...जारी

जैसे कि उत्तर में वर्णित है, 14 पेयजल टैस्टिंग प्रयोगशालाओं में कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। आप आऊटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहती हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के मानकों के अंतर्गत आऊटसोर्स आधार पर निविदाएं की गई हैं और 27 प्रयोगशालाओं का कार्य निजी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। **इसके अलावा विभाग में वॉटर टैस्टिंग स्टॉफ के भी 20 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 8 पद रिक्त हैं। आपने कम स्टॉफ की बात की है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें हमारे पास**

<u>स्टॉफ कम है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने की हम कोशिश करेंगे। विभाग का प्रयास रहेगा कि जल परीक्षण स्टॉफ की संख्या बढ़ाई जाए।</u> इस जल परीक्षण के संवेदनशील कार्य को हम निपुणता से करेंगे; इसमें समय लगेगा। एकदम इतने स्टॉफ को भरना संभव नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे यह हो जाएगा। आपके बहुत से सुझाव हैं जिनका मुझे पता है और मैं समझती हूं कि हम सबको उनका लाभ मिलना चाहिए। हमारी कोशिश है कि अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा करें।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर नहीं आया कि केवल 8 रिक्त पदों के कारण यह कार्य निजी क्षेत्र में देने का निर्णय किन कारणों से किया गया और यह निर्णय किस स्तर पर हुआ? इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि गत 3 वर्षों में जो आपकी अपनी विभागीय प्रयोगशालाएं हैं उनमें कितने सैंपल टैस्ट हुए, निजी क्षेत्र से कितने सैंपल टैस्ट करवाए गए और उनका परिणाम क्या रहा? मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप सुझाव के बजाये केवल प्रश्न पूछें।

श्री महेश्वर सिंह : जो आपका उत्तर है और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार प्रदेश स्तर पर आपकी कोई भी प्रयोगशाला नहीं है। क्या सरकार इस बात पर विचार

18.03.2016/1110/SLS-AS-2

करेगी कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राज्य स्तर पर एक अच्छी प्रयोगशाला हो। इन 41 प्रयोगशालाओं के स्थान पर इनको कम करके केवल सुदृढ़ करने का कार्य किया जाए और एक एक-एक प्रयोगशाला हर जिले में हो, क्या इस सुझाव पर विचार करेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। मैं भी इस बात को मानती हूं। हमें आपके सुझाव पर विश्वास है। लेकिन आप हर बार हमें कुछ-न-कुछ बताते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ ही कर दें। ऐसा संभव नहीं है। हर काम समय पर ही होता है। जैसे बजट है उसी के हिसाब से काम होगा। फिर हमें भारत सरकार की योजनाओं के मुताबिक भी काम करना पड़ता है और नियमों को भी

देखना पड़ता है। आप इस बात को गलत तरीके से ले रहे हैं कि हम इस पर सोचते ही नहीं हैं। क्या हमने पिछले 3 सालों में कोई काम नहीं किया? पानी को लेकर समस्याएं आईं थीं लेकिन जो समस्या पिछले वर्ष हुई उसके कारण आप सब लोग नाराज हैं। जनता भी नाराज होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो सैंपल हमने पूना लैब में टैस्टिंग के लिए दिया, उसमें हमने कोशिश की है। हम आऊटसोर्सिंग के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और लोगों को लाभ देंगे। आपका जो तजुर्बा है उसका भी हम लाभ उठाना चाहते हैं। हमारी भी ऐसी सोच नहीं है कि हम आपकी बात को न सुनें। जो हमारी स्टेट लैब है उसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जो सुझाव हैं उन पर बैठकर बात करने की ज़रूरत है। हमारी भी इसमें अपनी सोच है और जनता से भी सुझाव मिलते है। उन सुझावों पर बैठकर बात करने की ज़रूरत है; उसमें शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज को मज़बूत करने के लिए हम सबको तैयार रहना है। आप ऐसा मत समझिए कि पानी की कमी रही है। पिछले 3 सालों में बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे इस टैन्योर में इतना ज्यादा काम हुआ है कि इसमें शक की कोई गुंजाईश नहीं है। बाकी आपने कुछ और बताना है तो बता दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे।

अगला प्रश्न...गर्ग जी

18/03/2016/1115/RG/AS/1

प्रश्न सं.2980

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बहुत विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन जो प्रश्न का 'सी' भाग था कि 'How many posts of all categories are lying vacant and since when? इसमें माननीय मंत्री जी ने इकट्ठी करके फिगर दे दी है, '6,169 posts of all categories are lying vacant. लेकिन कैटागिरीवाईज नहीं दिया है। अगर हम इन 6,169 पदों को भी देखें, तो 30 या 31% पद स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं। क्योंकि इन्होंने बताया है कि 18,919 पद क्रियेटिड हैं। इन्होंने यह भी बताया है कि कुछ पद ऐसे हैं जोकि वर्ष 1970 से खाली हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो पद लगभग पिछले 46 सालों से खाली हैं क्या उनको भरने की कोई जरूरत ही नहीं है या विभाग में उनकी जरूरत नहीं है या किसलिए ये पद रखे गए हैं? दूसरा, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बारे पूछा था। इन्होंने बताया जो खाली पद हैं सलूणी में एक पद पिछले चार साल से खाली है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि एक तो मुझे यह समझ नहीं आया कि सी.एच.सीज़. में डॉक्टर्ज की स्ट्रैन्थ अलग-अलग क्यों है? सी.एच.सी., किहार में डॉक्टर्ज के चार पद स्वीकृत हैं और सी.एच.सी., सलूणी जोकि सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर का सी.एच.सी. है वहां दो ही पद हैं, लेकिन वहां एक ही डॉक्टर है और दूसरा पद चार साल से खाली है। इसी तरह से कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर, बाथरी में चार में से तीन पद रिक्त हैं, शायद कल एक एम.ओ. ने ज्वाईन किया है, तो दो पद रिक्त होंगे। क्या माननीय मंत्री जी इन सी.एच.सी. में anomaly को हटाने का आश्वासन देंगे और ये पद कब तक भर दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग में काफी पद खाली हैं और जो पद खाली हैं, उनका हमने विस्तृत तौर पर इसमें ब्योरा दिया है। कितने Institutions हैं, Institutions का भी हमने, मैडिकल कॉलेज का, जोनल हास्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल, सी.एच.सी, पी.एच.सी. और हैल्थ सब-सेन्टर्ज की भी डिटेल में, जो अनैक्श्चर लगाया है उसमें ब्योरा दिया गया है। किस जिले में कितने पद रिक्त है वह भी हमने अनैक्श्चर में दिया है। जहां तक इन्होंने कहा कि कब-कब से ये पद खाली हैं, तो हमने कहा कि वर्ष 1970 से लेकर ये पद खाली होते रहे हैं। कुछ पद इसलिए खाली हैं कि नए पद

18/03/2016/1115/RG/AS/2

हमने सृजित किए हैं, कुछ पद इसलिए खाली हुए हैं कि कुछ लोगों की सुपएनुएशन या रिटायरमेंट हो चुकी है, कुछ पद ऐसे हैं जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ पद ऐसे हैं जो पद किसी स्टाफ के रिजाईन देने से खाली हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि स्वास्थ्य विभाग में फंक्शनल पोस्ट्ज को हम जल्दी-से-जल्दी भरें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने पिछले तीन साल में काफी पद भरे हैं। यदि हम डॉक्टर्ज की बात करें, तो 772 डॉक्टर्ज हमने पिछले तीन वर्षों में लगाए हैं और जो बात है कि 147 डॉक्टर्ज

पी.जी. करने चले जाते हैं जिसके कारण उनके पद खाली हो जाते हैं। 309 Pharmacists हमने पिछले तीन साल में लगाए हैं, Ophthalmic Assistants लगाए हैं, Physiotherapist लगाए हैं, Staff Nurses लगाई हैं, Radiographers लगाए हैं, OTAs लगाए हैं और Laboratory Assistants लगाए हैं, Male & Female Health Workers लगाए हैं। कुछ पोस्ट्ज भरने के लिए हमने जैसे लोक सेवा आयोग को डॉक्टर्ज की पोस्ट्ज भरने और अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को पैरा-मैडिकल स्टाफ भरने की इजाजत दी है। अभी हम कैबिनेट में और मामले ले जा रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे Institutions खोले हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले तीन साल में 9 Health Sub-Centre खुले, 57 हमने Primary Health Centers खोले, 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6 बिस्तरों से 30 बिस्तरों के कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर्ज बनाए और 17, 30 बिस्तरों के कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर्ज से सिविल अस्पताल हमने बनाए हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

18/03/2016/1120/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2980 क्रमागत----स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी------

कुछ सिविल अस्पताल 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों के किए हैं और कुछ 100 बिस्तरों से 200 बिस्तरों के किए हैं। इस तरीके से बिस्तरों की संख्या में बढ़ोत्तरी की है। हमने नॉर्म्ज फिक्स कर दिए हैं कि यदि पी0एच0सी0 होगा तो उसमें कम-से-कम एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और एक क्लास फोर होगा। सी0एच0सी0 में चार डॉक्टर्ज होने चाहिए। अगर मैं पिछली सरकार के समय की नोटिफिकेशन निकालूं जिसमें सलूणी की सी0एच0सी0 भी शामिल है तो उस समय नई पोस्ट्स कोई भी क्रिएट नहीं की गई। सिर्फ बोर्ड लगा दिया कि इसे पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 बना दिया गया है, not even a single new post was created at that time, now we are taking steps to create posts in those institutions which are without posts.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, हर बार मंत्री जी की ओर से एक निर्धारित जवाब आता है चाहे प्रश्न कोई भी हो कि आपके समय में संस्थान खोल दिए गए लेकिन पोस्ट्स क्रिएट

नहीं की गई। मैं देख रहा हूं कि पिछले तीन वर्षों में संस्थान खोलने की रफ्तार बढ़ी है। हम संस्थान खोलने के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हैं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन संस्थान खोलने के साथ-साथ वहां पर स्टाफ का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। उन संस्थानों मेंर डॉक्टर्ज और फार्मासिस्ट्स नहीं पहुंच रहे हैं। उस वजह से जो खोले हुए संस्थान हैं वे बन्द होने की कगार पर आ गए हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री जय राम ठाकुरः जी सर। अध्यक्ष जी, 100 में से 33 पोस्ट्स खाली हैं अगर एवरेज निकाली जाए यानी लगभग 32 प्रतिशत से ऊपर पद खाली हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कहते हैं हमने संस्थानों को अपग्रेड किया तथा बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया। आप बिस्तरों की संख्या ही बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नये संस्थान खोले हैं क्या आपने इनमें पद भी क्रिएट कर दिए हैं? दूसरी बात, पद क्रिएट करना एक बात है। आप हर जगह कहते हैं कि हमने पद क्रिएट कर दिए हैं। अगर पद क्रिएट कर दिए हैं तो वहां पर नये संस्थान खोलने के बाद आपने कितने पद भरे हैं? मुझे यह जानकारी चाहिए और तीसरी बात, प्रश्न तो यह अलग तरह का था लेकिन इस प्रश्न में यह क्लब हो गया है

18/03/2016/1120/MS/DC/2

इसलिए कई चीजें इसमें शामिल हो गई हैं। मैं एक बात और जानना चाहता हूं। आपने तीन मेडिकल कॉलेज खोलने का जिक्र किया है। क्या इन तीनों मेडिकल कॉलेजिज के लिए पद भी क्रिएट कर दिए हैं क्योंकि मैं देख रहा था कि आप यहां से बदलकर वहां पद भरने जा रहे हैं। मुझे ये तीन जवाब पहले चाहिए बाकी की बातें उसके बाद करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारीः अध्यक्ष जी, मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा और मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि इनके वक्त में, मेरे पास नोटिफिकेशन की प्रति है। जो इन्होंने पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 बनाए हैं -(व्यवधान)- Have patience I will satisfy you. You don't worry. अध्यक्ष जी, हमने तीन सालों में जितने भी संस्थान खोले हैं उन सबमें हमने पद क्रिएट कर दिए हैं। नये नौ पी0एच0सीज0 जो मुख्य मंत्री जी ने अभी एनाऊंस किए हैं, उनकी केबिनैट से एप्रूवल हो गई है। उनके पदों का केस वित्त विभाग को

भेजा है और जैसे ही फाइनैंस से आएगा, अगली बार उन पदों को भी क्रिएट कर देंगे। बाकी जितने संस्थान हमने खोले हैं उन सबमें पद क्रिएट कर दिए हैं। जहां तक तीनों मेडिकल कॉलेजिज की बात है, ये न अभी ऑपरेशनल हुए हैं और न ही इनके लिए हमने स्टाफ दिया है। हमने अपने रिप्लाई में सिर्फ दो मेडिकल कॉलेजिज शो किए हैं और उनमें जो पद खाली हैं उनके बारे में भी बताया है। जो तीन मेडिकल कॉलेजिज खोलने की बात है उनमें जो पद क्रिएट किए जाते हैं उनकी स्वीकृति के लिए मामला पहले वित्त विभाग में जाता है और फिर वहां से केबिनैट में आता है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज चम्बा और नाहन के लिए काफी पदों की स्वीकृति दे दी है और उन पोस्ट्स को भरने का काम जारी कर दिया है। तीन मेडिकल कॉलेजिज में से दो में पोस्ट्स क्रिएट करने का काम हो चुका है और अब हमने ये केस भेजा है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, पद भरना एक निरंतर प्रक्रिया है।

जैसे मैंने कहा कि कुछेक पद हम क्रिएट करते हैं, कुछ पर प्रमोशन्ज हो जाती हैं, कुछ सुपरन्युएशन होती है, कुछ डैथ हो जाती है और कुछ रिटायरमैंट ले लेते हैं तो उस वजह से ये पद खाली भी होते रहते हैं और भरने का प्रोसैस भी जारी है। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

18.03.2016/1125/जेएस/DC/1

प्रश्न संख्याः 2980:-----**जारी**------

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः-----**जारी**------

इनको और बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी है। जो पोस्टें खाली हैं, फंक्शनल पोस्टें हैं उन पोस्टों को भरने के प्रयास सरकार कर रही है।

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष माहदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो डिटेल्ज इन्होंने यहां पर दे रखी है उसके अनुसार लगभग 2000 posts of all the categories are lying vacant in the State of all the health institutions. I don't

know how the Health Minister is managing with this much strength, which he is already having at his disposal और इसी का कारण है कि आज जगह-जगह महामारी और पीलिया फैल रहा है, क्योंकि डॉक्टर्ज़ अवेलेबल नहीं है। लोग झाड़-फूंक करने वाले देसी वैद्यों के पास जा रहे हैं इस पर भी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यह बड़ी हैरानी की बात है। कब तक इन पोस्टों को भर दिया जाएगा? मैं, माननीय मंत्री जी से इसके बारे में आश्वासन चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने कहा कि पोस्टों के भरने का प्रोसैस जारी है। जैसे कि अभी हमने 50 पोस्टे कॉंट्रैक्ट बेसिज़ पर पब्लिक सर्विस कमिशन को भरने की इज़ाजत दे दी है। पहली अप्रैल के बाद हर मंगलवार को डॉक्टर्ज की वॉक इन इंटरव्यू होगी और उसके बाद जो भी डॉक्टर्ज़ हमारे पास जहां से भी आएंगे उनको हम रिक्रूट करेंगे तथा उनको लगाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमने स्टाफ नर्सिज़ के 381 पद सबोर्डिनेट सर्विसिज़ सलैक्शन बोर्ड, हमीरपुर को भेज दिए हैं, जिसमें से 192 पोस्टें सबोर्डिनेट सर्विसिज सलैक्शन बोर्ड की होंगी, 35 पोस्टें डायरैक्टर सैनिक वैल्फेयर की होगी, 7 पोस्टें डायरैक्टर यूथ सर्विस एण्ड स्पोर्टस की होगी और 121 पोस्टें सबोर्डिनेट सर्विसिज सलैक्शन बोर्ड को इस तरह टोटल 381 पोस्टें भेज दी है। फीमेल हैल्थ वर्कर की 99 पोस्टें सबोर्डिनेट सर्विसिज सलैक्शन बोर्ड को भेज दी है। फार्मासिस्ट की भी 80 पोस्टें हैं,

18.03.2016/1125/जेएस/DC/2

जिनमें से 40 पोस्टें बैचवाईज़ भरेंगे और 40 पोस्टें सबोर्डिनेट सलैक्शन बोर्ड को भेज दी गई है। इसी तरह से रेडियोग्राफर की भी 30 पोस्टें भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ओ0टी0एस0 की भी 26 पोस्टें भरने जा रहे हैं। इसलिए यह कंटिन्यूस प्रोसैस है। जैसे-जैसे पोस्टें खाली होती रहेंगी सरकार का प्रयास होगा, इन पोस्टों को भरने के प्रयास किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा जो हम नए पी0एच0सीज0 खोल रहे हैं उनको फंक्शनल तब तक नहीं करेंगे जब तक जितने पी0एच0सीज0 और सी0एच0सीज0 पुराने हैं उनमें डॉक्टर्ज़ की पोस्टें न भर देते।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से ज़वाब देने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि ये पोस्टें वर्ष 1970 से वर्ष 2016 तक खाली हुई है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि वर्ष 1970 और उससे पहले इस प्रदेश के अन्दर कितने स्वास्थ्य संस्थान थे? उन स्वास्थ्य संस्थानों में कितनी पोस्टें वर्ष 1970 में खाली थी?

दूसरे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पोस्टें इस करके खाली होती रहती हैं कि कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है और करूणामूलक आधार पर भरनी होती है, तीसरे आपने कहा कि वलंटियर रिटायरमैंट ले लेते हैं उसके आधार पर खाली होती है। क्या ऐसे कितने केसिज़ है करूणामूलक आधार पर जो भरने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं भरे हैं और जिनकी वज़ह से पोस्टें खाली हैं? ऐसी कितनी पोस्टें हैं जिन्होंने वी0आर0एस0 लिया और उसके बाद वे पोस्टें खाली हैं? इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर ऐसे कितने स्वास्थ्य संस्थान हैं जिसमें जितनी पोस्टें होनी चाहिए थी उन पोस्टों में से कोई भी पोस्ट वहां पर नहीं है?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

18.03.2016/1130/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 2980 क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

उदाहरण के रूप में पी0एच0सी0 में डॉक्टर्ज़ नहीं हैं, पी0एच0सी0 में पैरा-मेडीकल स्टाफ नहीं है। जो हमारे हैल्थ सब-सैंटर्ज़ हैं वहां पर न मेल हैल्थ वर्कर्ज़ हैं और न फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़ हैं। क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ऐसे कितने इंस्टिट्यूशन्ज़ हैं जहां पर ऐसी स्थिति है?

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस प्रदेश के अंदर जो पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, रैफरल हॉस्पिटल या रूरल हॉस्पिटल के नॉर्म्ज़ थे, उनमें आपने कैटेगिराइज़ किया है कि पहले जिस पी0एच0सी0 में ज्यादा पोस्टें थीं उसको "बी" श्रेणी में डालकर पोस्टें कम कर दी गईं और वहां से स्टाफ दूसरी जगह भेज दिया? क्या आपके पास ऐसी सूचना है? अगर है तो क्या माननीय मंत्री जी उस सूचना को इस माननीय सदन में देने की कृपा करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य 1970 से पहले की सूचना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्रश्न करें। अगर यह चाहेंगे तो हम यह सूचना भी दे सकते हैं कि 1970 के बाद किन-किन सालों में कितनी-कितनी पोस्टें खाली होती रही हैं। मैंने करूणामूलक आधार का कोई रैफरैंस नहीं दिया और न ही हमने हैल्थ डिपार्टमैंट में किसी को वॉलंटरी रिटायरमैंट दी है। हमने यह भी कहा है कि जितने भी स्पैशलिस्ट हैं उनको हम प्री-मिच्योर रिटायरमैंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर 20 साल के बाद इसे लेना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए पहले इंस्ट्यिूशन्ज़ में जितनी पोस्टें सैंक्शन थीं हमने उनकी कोई पोस्ट खत्म नहीं की है। लेकिन यह फैसला ज़रूर लिया है कि आई0पी0डी0 और ओ0पी0डी0 जिन पी0एच0सीज़0 और सी0एच0सीज़0 में जितनी हैं उसके मुताबिक वहां पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। हमने कोई पोस्ट कम नहीं की है। इनके वक्त में जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें न पी0एच0सी0 में पोस्टें क्रियेट कीं और न ही सी0एच0सी0 में क्रियेट कीं और न ही सिविल हॉस्पिटल में की हैं।

18.03.2016/1130/SS-AG/2

लेकिन हम जो भी स्वास्थ्य संस्थान क्रियेट या अपग्रेड कर रहे हैं उनमें पोस्टें साथ ही सैंक्शन कर रहे हैं। यह मैं माननीय सदन में कहना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य अगर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित करूणामूलक आधार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्रश्न करें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़ की बात है यह ठीक है कि हमारे पास लगभग 2067 के करीब हैल्थ सब-सैंटर्ज़ हैं। उसमें मेल हैल्थ वर्कर्ज़ की ट्रेनिंग पिछले कई

सालों से नहीं हुई है और न ही हमारे पास मेल हैल्थ वर्कर हैं। हमने 112 मेल हैल्थ वर्कर्ज़ जो इम्प्लॉयमैंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थे, कैबिनेट से एप्रूवल करवाई और कैबिनेट से एप्रूवल करवाने के बाद सबोर्डिनेट सिलैक्शन बोर्ड को मामला भेजा लेकिन उसमें से 57 ही योग्य पाए गये। जो 57 आए उनको हमने लगा दिया है। अब हमने फैसला किया है कि मेल हैल्थ वर्कर्ज़ की ट्रेनिंग भी हिमाचल प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। हम कम-से-कम 300 मेल हैल्थ वर्कर्ज़ को ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़ की 99 पोस्टें सबोर्डिनेट सिलैक्शन बोर्ड को भेजी हैं, जैसे ही ये पोस्टें वहां से सिलैक्ट हो कर आयेंगी, हम उन्हें उन इंस्टिट्यूशन्ज़ में लगायेंगे, जिन इंस्टिट्यूशन्ज़ में न मेल हैल्थ वर्कर है और न फीमेल हैल्थ वर्कर है। उन संस्थान को प्राथमिकता दी जायेगी। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपका सहयोग मिला तो हम निश्चित तौर पर सभी इंस्टिट्यूशन्ज़ को भरने की कोशिश करेंगे।

अभी आपने पूछा कि कितने संस्थान ऐसे हैं जो बिना एम0ओ0 के हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में 37 पी0एच0सीज़0 ऐसी हैं जो बिना डॉक्टर और फार्मासिस्ट के हैं। प्रदेश के अंदर 121 हैल्थ सब-सैंटर्ज़ ऐसे हैं, जहां न मेल हैल्थ वर्कर है, न फीमेल हैल्थ वर्कर है और उनमें ताले लगे हैं। इसलिए हमने 100 फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़ की पोस्टें भर्ती करने के लिए भेजी हैं। जैसे मैंने कहा कि मेल हैल्थ वर्कर्ज़ की हमारे पास लगभग एक हजार पोस्टें खाली हैं, उन पोस्टों को भरने के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है ताकि हम सभी हैल्थ सब-सैंटर्ज़ में स्टाफ दे सकें।

18.03.2016/1130/SS-AG/3

Speaker: Next question, Shri Inder Singh. No, No. इन्होंने काफी डिटेल में कह दिया है। इन्होंने पूरा उत्तर दे दिया। Shri Inder Singhji, say your question. Elaborate answer has been given by the Hon'ble Health & Family Welfare Minister. What do you want to ask?

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐसे स्वास्थ्य संस्थान जहां पर न डॉक्टर्ज़ हैं, न पैरा-मेडीकल स्टाफ है और न ही अन्य स्टाफ है क्या माननीय मंत्री जी इन संस्थानों को चलाने

के लिए सिस्टम को रेशनलाईज़ करेंगे ताकि वहां कम-से-कम एक डॉक्टर तो अवश्य हो जाए, पैरा-मेडिकल स्टाफ हो जाए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ***अध्यक्ष महोदय, रेशनलाईज करने का प्रोसैस जारी है, उसको करेंगे।***

अगला प्रश्न जारी श्रीमती के0एस0

18.03.2016/1135/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2981

Shri Inder Singh: Sir, I am surprised with the reply which I have got to this question. मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी मिसलीड कर रहे हैं। नोमैन्क्लेचर के नाम पर टालमटोल कर रहे हैं। आप इसको इन्सपैक्शन हट कहिए या वन विश्राम गृह कहिए लेकिन मतलब तो वही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक तो मेरे चुनाव क्षेत्र पटड़ीघाट में एक नया वन विश्राम गृह बन रहा है that is not yet complete. इसी वन मण्डल में पांवटा में एक वन विभाग का विश्राम गृह बनना था, उसके लिए ढाई लाख रु0 बहुत साल पहले विद्ड्रा किया गया है और उसको स्पैंड कर दिया गया है लेकिन on the ground कोई सामान नहीं खरीदा गया है। कागजों में 27 हजार ब्रिक्स खरीदी गई हैं और 6 क्विंटल सरिया खरादी गया है लेकिन on the ground कुछ भी नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करवाएंगें कि वह पैसा कौन खा गया? रखोटा विश्राम गृह में वर्ष 2014-15 में 1 लाख रुपया रिपेयर करने और फर्निचर खरीदने के लिए दिया और इस साल साढ़े तीन लाख रु0 दिए गए हैं। आप कहते हैं कि इनके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि आपकी सूचना आधी-अधूरी है।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, कांगू का गलू विश्राम गृह श्री महेन्द्र सिंह जी के चुनाव क्षेत्र में है, उसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ उससे पहले ही वह गिर रहा है। तो इस चीज़

की इन्क्वायरी करवाएंगें कि आपके विभाग में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके साथ ही थोना में एक आपकी इंस्पैक्शन हट है या वन विश्राम गृह है, वह गिरने की कगार पर है। यह असैट्स हमें पीछे से मिली हैं why don't you maintain them? यह भी मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। सुकेत वन मण्डल में नेहरी में एक रैस्टहाऊस वर्ष 2006 से बन रहा है और अभी तक भी वह कम्पलीट नहीं हुआ है। आप सूचना दे रहे हैं कि शून्य है तो why are you misleading the House?

18.03.2016/1135/केएस/एजी/2

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी अब इस हाऊस के वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने रैस्ट हाऊसिज़ की बात की है। वन विभाग में दो तरह के कंस्ट्रक्शन्ज़ हैं। एक रैस्ट हाऊस है, एक इन्सपैक्शन हट्स हैं। हमें सूचना छिपाने में कोई दिलचस्पी नहीं हैं लेकिन इन्होंने प्रश्न जिस ढंग से पूछा है, उसी ढंग से जवाब दिया गया है। आगे ये सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं और इनका मूल प्रश्न वन मण्डल सुकेत को ले कर है। अभी इन्होंने पूरे ही हिमाचल का पक्ष रख दिया। पांवटा का रख दिया। जहां तक सुकेत वन मण्डल की बात है जिसके बारे में आपने सवाल पूछा है, सुकेत वन मण्डल के तहत इन्सपैक्शन हट है कुटीर-बागी-पांवटा , यह वर्ष 2004-05 में मंजूर किया गया था और इसके लिए 33 लाख रुपये वर्ष 2008 में व्यय किए गए। इसमें दो कमरे हैं। इसके बाद यह मामला अदालत में चला गया और माननीय अदालत में यह काफी दिनों तक लम्बित रहा। हाल ही की सूचना के मुताबिक 10.07.2015 को यह मामला खारिज हो गया। इसमें हम पता करवा लेंगें कि बाकी कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। इसका ऐस्टिमेट 7 लाख 91 हजार रु0 था इसमें से 3 लाख रु0 खर्च कर दिया गया है। हमारे पास इसके 4 लाख 91 हजार रु0 पड़े हैं। हम इसका स्टेटस पता करवा लेंगें और यह पैसा वहां लगवा देंगें।

इसके अतिरिक्त वन निरीक्षण कुटीर-कुठाई सुन्दरनगर में हैं। इसमें वर्ष 2015-16 में 15 लाख 18 हजार रुपया सेंक्शन हुआ था। इसमें प्रस्तावित कमरों की संख्या तीन है और इस पर अभी 2 लाख रु0 खर्च किए गए हैा । जो बजट अभी पेश हुआ है, हमने इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से बजट मांगा है जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा, इसका हम निर्माण कर देंगें। रैस्ट हाऊसिज़ और इन्सपैक्शन हट्स के ऊपर टोटल वन विभाग 3 करोड़ रु0 खर्च करता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.3.2016/1140/av/as/1

प्रश्न संख्या : 2981---------- क्रमागत

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत)-------- जारी

वन विभाग के पास यह बहुत लम्बी-चौड़ी ऐस्टेब्लिशमैंट हो गई है क्योंकि कुल 453 रैस्ट हाउसिज और इनस्पैक्शन हट्स हो गये हैं। 281 रैस्ट हाउसिज और 172 इनस्पैक्शन हट्स हैं तथा इनका रख-रखाव करना वैसे भी एक चुनौती बना हुआ है।

श्री इंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो पांवटा का जिक्र किया है उसमें कोई सामान नहीं खरीदा गया है। On the ground nothing has been purchased there and on the papers मैं ढाई लाख बोल रहा हूं और मंत्री जी तीन लाख रुपये बोल रहे हैं। इस बारे में जांच करवाई जाए कि यह पैसा किसकी जेब में गया। कांगू-रा-गलू के रैस्ट हाउस का फर्नीचर भी वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के घरों में लगा हुआ है, उसकी भी जांच करवाई जाए। रखोटा के रैस्ट हाउस के लिए आपने जो अभी 3.50 लाख रुपये दिए हैं और एक लाख रुपये पहले के दिए हुए हैं उसका भी मिसयूज हो रहा है। कृपया उसकी भी जांच करवाइए। इसके अतिरिक्त थोना की इनस्पैक्शन हट की रिपेयर के लिए कुछ पैसा दीजिए नहीं तो वह गिर जायेगी।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो तीन लाख रुपये की बात हो रही है तो यह राशि वर्ष 2004 में लगी थी। अब उसको 10-12 साल हो गये हैं। उस समय तीन लाख रुपये लगे हैं, अब उसकी क्या जांच करवायें। लेकिन उसके लिए जो फ्रैश 4.91 लाख रुपये की राशि आबंटित है उससे इसलिए खरीद-फरोक्त नहीं हुई क्योंकि अदालत में मामला लम्बित था। यह मामला अगस्त, 2015 में अदालत से हल हुआ है। यह पैसा हम लगा देंगे। यदि आपका कोई फर्नीचर फॉरैस्ट ऑफिसर/कर्मचारी के घर में लगा है तो हम विभाग को निर्देश दे देंगे कि उस फर्नीचर को मंगा कर रैस्ट हाउस में लगाया जाए।

18.3.2016/1140/av/as/2

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर जवाब दिया कि प्रदेश में वन विभाग के कुल 453 निरीक्षण कुटीर और विश्राम गृह हो गये हैं। माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश का जवाब दे दिया है। मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि जब किसी माननीय विधायक या प्रदेश के किसी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इनकी बुकिंग का क्राइटीरिया क्या है? यहां पर जब कोई बुकिंग के लिए बोलता है तो वहां से सीधा सा जवाब आता है कि यह वन मंत्री के नाम से बुक है।

Speaker : This is not relevant. It is not part of the question. This is another issue. Please sit down. The Minister need not to answer to this question, it is not relevant.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, रेलीवैंट है। कभी आपका पालमपुर वाला चाहिए होता है तो यह मिलता ही नहीं। जब यह वन मंत्री के नाम से बुक रहेंगे तो इनको बनाने का औचित्य क्या है? इनको किसके लिए बनाया जा रहा है। वहां पर अधिकारी होते हैं या यह चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए बुक होते हैं। एक बार प्रैस वालों को मना कर दिया कि आपको कमरे नहीं मिलेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वन विश्राम गृह या निरीक्षण कुटीर की बुकिंग डी0एफ0ओ0 करते हैं। अगर माननीय सदस्य को कहीं समस्या हुई है तो हम अपने डी0एफ0ओ0 से कहेंगे कि माननीय सदस्य का ठीक से ख्याल रखा जाए।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब भी बुकिंग के लिए पूछा जाता है तो जवाब आता है कि यह वन निगम के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के नाम से बुक है। ऐसे हालात पूरे प्रदेश के बने हुए है। आपको निर्णय करना होगा कि बुकिंग कहां से होगी और बुकिंग करनी है तो कौन करेगा? प्रश्न यह है कि लोक निर्माण विभाग और आई0पी0एच0 विभाग में दिक्कत नहीं आती फिर वन विभाग में इस प्रकार की दिक्कत क्यों आ रही है?

18.3.2016/1140/av/as/3

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि रविन्द्र जी बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं और इनका खास ख्याल रखा जायेगा।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरा ध्यान रखा जाए बल्कि मैं यह पूरे प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए पूछ रहा हूं।

श्री महेन्द्र सिंह टी सी द्वारा जारी

18.03.2016/1145/TCV/AS/1
प्रश्न संख्याः 2981-- क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी जहां तक सुकेत वन मण्डल का प्रश्न है, सुकेत वन मण्डल के अन्दर बहुत से इन्सपैक्शन हट बने हुए हैं और जो इन्सपैक्शन हट बने हुए हैं, जिनका जिक्र माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने भी किया है, मैं भी इनके बारे में आपके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इन्सपैक्शन हट बन गये और वहां पर फर्नीचर इत्यादि रख दिया गया लेकिन उन इन्सपैक्शन हट की चौकीदारी के लिए कोई भी व्यक्ति तैनात नहीं किया गया है। दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे इन्सपैक्शन हट जो दूरदराज के जंगलों के बीच में बने हुए हैं, उदाहरण के रूप में एक इन्सपैक्शन हट 'डाबरू-का-डवार' जिसमें टूरिज्म डिपार्टमैंट से पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमैंट को गया है और यह सुकेत वन मण्डल के अन्तर्गत बना है। वह इन्सपैक्शन हट सड़क से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अभी उस तक पहुंचने के लिए न कोई ब्राईडल पाथ है और न कोई दूसरी आने जाने की व्यवस्था है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वन विभाग के जहां-जहां ऐसे इन्सपैक्शन हट बने हैं, उन इन्सपैक्शन हट के लिए स्पेसिफिक किसी सड़क से वहां तक पहुंचने के लिए ब्राईडल पाथ बनाने के आदेश विभाग को देंगे?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्राईडल पाथ है, ये फॉरेस्ट के स्टॉफ और राईट हॉल्डर्ज के लिए होते हैं। माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक स्थान बताएंगे तो उसकी पड़ताल कर लेंगे कि किस तरह वहां तक रास्ता पहुंचाया जा सकता है।

18.03.2016/1145/TCV/AS/2

प्रश्न संख्याः 2982

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के "ए" भाग का जवाब दिया है कि 2 ट्रामा सेंटर चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनको खोलने का क्या क्राइटिरिया है? इस प्रश्न के "बी" भाग में इन्होंने जवाब दिया है कि Whether the government planned to open new Trauma Centre? 'Yes' तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अम्ब में जहां पर नवरात्रों में बड़ी ट्रैफिक होती है और दूसरे जब बड़भाग सिंह का मेला होता है, उस समय भी वहां बड़ी भारी ट्रैफिक होती है और आये दिन ऐक्सिडेंट्स होते रहते है। क्या मंत्री जी वहां भी ट्रामा सेंटर खोलने का आश्वासन देंगे?

स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो "बी" भाग में 'यस' कहा है, उसमें अभी तक ट्रामा सेंटर डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा, लैवल-2, जोनल हॉस्पिटल मण्डी, लैवल-3, रीजनल हॉस्पिटल, हमीरपुर, लैवल-3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चम्बा, लैवल-3 और एम0जी0एम0एस0सी0, खनेरी, रामपुर लैवल-3 सैंक्शन हुए है। इस प्रकार से ट्रामा सेंटर खोलने की स्कीम भारत सरकार ने अभी तक नेशनल हाईवेज़ को कवर करने के लिए ही बनाई है। हम भारत सरकार को केस भेजतें हैं और वह इसकी स्लैक्शन करती है। उसके मुताबिक ही भारत सरकार ने ये 5 नये ट्रामा सेंटर हिमाचल प्रदेश को सैंक्शन किए हैं।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि इन्होंने ये जो 5 ट्रामा सेंटर्ज बताये हैं और इनमें से एक चम्बा का भी है। क्या कारण है कि यह जो ट्रामा सेंटर है यह अभी तक सैटअप नहीं हो सका और क्या आप

इसको चम्बा हॉस्पिटल में सैटअल करने वाले हैं या अलग से कहीं ट्रामा सेंटर बनाएंगे, क्योंकि चम्बा हॉस्पिटल नेशनल हाईवे पर नहीं है?

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

18.03.2016/1150/RKS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2982...क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने ट्रॉमा सैंटर को चम्बा रीजनल हॉस्पीटल के लिए सैंक्शन किया है। चम्बा रीजनल हॉस्पिटल के साथ ही ट्रॉमा सैंटर बनाने के लिए जमीन मंजूर हो गई है। 4 ट्रॉमा सैंटर की कंस्ट्रक्शन के लिए 81-81 लाख रुपया केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है। डा0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कोलेज, टांडा के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 1 करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपया मंजूर कर दिया है। चम्बा में इक्वेपमेंट के लिए 1 करोड़ 94 लाख 40 हजार रुपया मंजूर कर दिया है। इस हिसाब से सब ट्रॉमा सैंटर के लिए पैसा मंजूर किया गया है। कुल मिलाकर कंस्ट्रक्शन के लिए 4 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपए, इक्वेपमेंट के लिए 12 करोड़, 63 लाख 60 हजार रुपया और कुल मिलाकर ए.एल.बी. के लिए 17 करोड़ 9 लाख 10 हजार रुपए पैसा मंजूर हो चुका है।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष जी, नेशनल हाईवेज के ऊपर ट्रॉमा सैंटर बनाने की सरकार की पॉलिसी है। Nurpur is a very important center.यह 5 निर्वाचन क्षेत्र का सेंटर पड़ता है । दो साल पहले बजट में यह घोषणा हुई थी कि नूरपुर में ट्रॉमा सैंटर बनेगा। जब केंद्र में ट्रॉमा सैंटर की लिस्ट गई तो उसमें नूरपुर का नाम नहीं था। इस सदन में जब मैंने रिक्वेस्ट की तो माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि नूरपुर का नाम केंद्र को भेजा जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नूरपुर ट्रॉमा सैंटर की स्कीम केंद्र को भेज दी गई है या नहीं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हमने नूरपुर ट्रॉमा सैंटर के अलावा और भी ट्रामा सैंटर मंजूर करने के लिए केंद्र को भेजे थे, जिनकी सूची मेरे पास नहीं है। अब नेशनल हाईवे के 100 किलामीटर पर एक ट्रॉमा सैंटर खोला जाएगा।

Unfortunately or fortunately, Nurpur is near Pathankot. इसलिए अभी it did not find favour with Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. हम दोबारा इसको टेक अप करेंगे। इसके बारे में हम केंद्र सरकार से दोबार अनुरोध करेंगे। इसके अलावा जो अन्य इम्पोरटैंट स्टेशन रह गए हैं उन स्थानों के बारे में भी अनुरोध किया जाएगा।

18.03.2016/1150/RKS/DC/2

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ट्रॉमा सैंटर के लिए सरकार नैशनल हाईवे के ऊपर कंसीडर करती है। जो मैंन अम्ब का नाम दिया है वह भी नेशनल हाईवे के ऊपर है। वहां पर नवरात्रों में बड़भाग के मेले में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है और आए दिन वहां ट्रैफ्कि ऐक्सिडेंट भी होते रहते हैं। क्या सरकार अब, जो प्रपोजल भेजेगी उसमें अम्ब का नाम भी रिकमेंड करेगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। अम्ब एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अम्ब का डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टरज ऊना है। भारत सरकार रीजनल हॉस्पिटल में ही ट्रॉमा सैंटर सैंक्शन करती है। हम कोशिश करेंगे अगर ऊना में ट्रॉमा सैंटर खुल गया तो, It will fulfill the needs of people of Amb area.

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने हमीरपुर और टांडा में ट्रॉमा सैंटर की बात कही। NH-88 में ज्वालामुखी स्थित है, जोकि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हर रोज लाखों लोग वहां माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। देहरा से लेकर ज्वालामुखी और चिंतपुरनी से लेकर देहरा तक की सड़कों में काफी एक्सीडेंट होते रहते हैं। ज्वालामुखी केंद्र में स्थित है। क्या जो अगली लिस्ट केंद्र सरकार को जाएगी उसमें ज्वालामुखी को शामिल किया जाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अम्ब और ज्वालामुखी के बारे में जिक्र हुआ। अम्ब के नजदीक चिंतपुरनी है। ज्वालामुखी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। हम इनके

लिए कोशिश करेंगे। हम तो केवल केस रिकमेंड कर सकते हैं। इनकी मंजूरी के लिए भारत सरकार की अप्रूवल जरूरी है। नेशनल हाइवे के नजदीक जो भी 50 किलोमीटर पर है

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

18.03.2016/1155/SLS-DC-1

प्रश्न संख्या : 2982...जारी

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी

हम उस केस को दोबारा से केंद्र सरकार से टेक अप करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमें ज्यादा-से-ज्यादा ट्रौमा सैंटर्ज़ मिलें। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है। यहां जब दुर्घटना होती है तो उसमें बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज होती हैं। हमारी कोशिश है कि जो प्रिवैंटेबल डैथ्ज हैं उन्हें 10 परसैंट तक पहुंचाया जाए और जहां ट्रौमा सैंटर्ज़ होंगे वहां निश्चित तौर पर इसमें लाभ मिलेगा।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और IGMC हिमाचल प्रदेश का Premier Hospital है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शिमला में ट्रॉमा सैंटर खोलने का इनका कोई प्रस्ताव है। पिछले दिनों इंडस हॉस्पिटल को टेक ओवर करके उसको IGMC के अधीन करके ट्रौमा सैंटर बनाने का प्रस्ताव था। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि शिमला में IGMC में या इंडस हॉस्पिटल को किसी भी प्रकार से टेक ओवर करके इस Premier Hospital में ट्रौमा सैंटर खोलेंगे। आप टाण्डा में और दूसरी सब जगहों पर खोल रहे हैं। शिमला में सारे प्रदेश से रोगी आते हैं, क्या यहां पर भी ट्रौमा सैंटर खोलने का आपका प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर शिमला में IGMC हमारा सबसे पुराना हॉस्पिटल है जो 1966 से चल रहा है और इसे स्टेट हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है। हम चाहते हैं कि IGMC में जल्दी-से-जल्दी ट्रौमा सैंटर खोला जाए। लेकिन दुर्भाग्य से IGMC में जगह उपलब्ध नहीं थी। यहां लेवल-1 का ट्रौमा सैंटर खुलेगा। दूसरे लेवल-2 और लेवल-3 के हैं। इसके लिए हमने इंडस हॉस्पिटल के साथ पी.पी.पी. मोड पर MoU भी साईन कर लिया है। भारत सरकार की टीम भी उसकी इंस्पैक्शन कर

चुकी है और यह एल-1 ट्रौमा सैंटर बहुत जल्दी IGMC attached Indus Hospital के साथ खुलेगा। इसके लिए केंद्र

18.03.2016/1155/SLS-DC-2

सरकार बहुत ज्यादा पैसा देती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसका पैट्रन 90:10 का है यानी 90 प्रतिशत भारत सरकार देती है और 10 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार का होता है। **हमारी कोशिश होगी कि IGMC का ट्रौमा सैंटर जल्दी-से-जल्दी इंडस हॉस्पिटल में खुले ताकि यहां पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उनमें लोगों को राहत मिले। इसे हम जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे।**

18.03.2016/1155/SLS-DC-3

प्रश्न संख्या : 2983

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इसमें 3-4 रेंजों के ब्राईडल पाथ दर्शाए गए हैं, लेकिन इनके रख-रखाव के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्या जो जंगलों को आग इत्यादि से बचाने के लिए और पैदल चलने के लिए जो पुराने ब्राईडल पाथ थे, इनके रख-रखाव के लिए आप धन का प्रावधान करेंगे? दूसरे, क्या अगर कोई विधायक विधायक निधि से ब्राईडल पॉथ बनाने के लिए पैसा देगा तो सरकार उसके लिए अनुमति देगी?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, जंगलों के ब्राईडल पॉथ के लिए पिछले बजट में 35 लाख रुपया रखा गया था। उत्तर में यहां आपकी ही सूची है जिसमें आपके ही 42 स्थानों पर यह पैसा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको कोई और स्पैस्फिक लोकेशन लगे तो उसके बारे में आप हमें बताएं, हम उस पर अमल करेंगे।

18.03.2016/1155/SLS-DC-4

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : श्री बी.के. चौहान जी, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री बी.के.चौहान : सर, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में आज दैनिक जागरण में लगी ख़बर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसका हैडिंग है

...(व्यवधान)...

जारी ...गर्ग जी

18/03/2016/1200/RG/AG/1

श्री बी.के. चौहान---क्रमागत

'अब चम्बा की सात पंचायत में पीलिया फैला, 15 बीमार।' सिर्फ 15 बीमार ही नहीं, एक आदमी की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मैंने कल बजट पर चल रही चर्चा के दौरान भी विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि चम्बा में जो भी पानी है, नदी-नालों से सीधा पाईप से पिलाया जा रहा हैं, गांवों में भी और कुछ हद तक शहरों में भी। सारे जितने भी स्रोत हैं वहां कोई फिल्टर बेड्ज नहीं है। वहां से पानी सीधे टैंक में जाता है और टैंक से पानी लोगों के घरों में जाता है। इससे पहले कि यह महामारी का रूप धारण करे, मेरा आग्रह है कि इस पर अविलम्ब उचित कार्रवाई की जाए और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को यह हिदायत दी जाए कि पानी टैंक तक पहुंचने से पूर्व स्रोत पर ही फिल्टर बेड्ज बनाकर भेजा जाए। क्योंकि एक भी गांव में जो भी पानी दिया जा रहा है, unfiltered water दिया जा रहा है और भगवान न करे कि यह फैलते-फैलते सारे चम्बा जिले में फैल जाए। इसलिए इसमें सरकार उचित कार्रवाई करे, मुझे यही आश्वासन चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री कृपया इसका जवाब दीजिए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, मैंने इनकी बात को अच्छी तरह से समझ लिया और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी इस काम को पूरा किया जाए ताकि वहां की जनता को इस समस्या से निजात मिले। उन्हें पीने का ठीक साफ पानी मिले। जो आपने कहा, मैंने उसको समझ लिया और **as early as possible, I will get it done. Thank you.**

18/03/2016/1200/RG/AG/2

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

अध्यक्ष : श्री बिक्रम सिंह जरियाल जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री बिक्रम सिंह जरियाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय भी पीलिया के बारे में ही है। आज मेरा प्रश्न संख्या 1277 लगा हुआ था। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 174 पेयजल योजनाएं ग्रेविटी लाईन की हैं और दो L.W.S.S. की हैं। इसमें कहीं भी फिल्टर बेड्ज नहीं हैं, वाटर ट्रीटमेंट नहीं है और टैंक्स खुले हैं, न उनकी सफाई होती है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदया से आश्वासन चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र भटियात में जो 174 पेयजल की ग्रेविटी की योजनाएं और दो L.W.S.S हैं क्या इनमें फिल्टर बेड्ज या वाटर ट्रीटमेंट लगाने के आदेश देंगी?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा, मैं इनकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई। **<u>As I said just now, we will get it done as early as possible</u>**. आपको एकदम से तो मैं कह नहीं सकती हूं, लेकिन जैसा इन्होंने कहा, **<u>उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। मैं यह बात आपको विश्वास के साथ कहना चाहती हूं। जल्दी-से-जल्दी हम इसको करेंगे।</u>**

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पीलिया रोग न फैले, इसके लिए आप कोई कदम उठाएं। बाकी काम तो होते रहेंगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है।

18/03/2016/1200/RG/AG/3

<u>कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे</u>

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय सहकारिता मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सहकारिता मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः आयु0-क-(3)-20/99 दिनांक 03.04.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.05.2013 को प्रकाशित;

ii. हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः आयु0-क-(3)-5/97-पार्ट-1 दिनांक 20.09.2013, 03.01.2015 तथा दिनांक 22-09-2015 (संशोधनों सहित) द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.09.2013 तथा 04-02-2015 को प्रकाशित;

iii. हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, स्टाफ नर्स, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याःआयु0-क-(3)-6/99 दिनांक 30.05.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.07.2013 को प्रकाशित; और

iv. हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, सहायक परिचारिका दाई, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः आयु0-क-(3)-25/99-पार्ट दिनांक 07.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2015 को प्रकाशित ।

(i) **से** (iv) **तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है**)

18/03/2016/1200/RG/AG/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। सर्वप्रथम श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति(2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **135वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा)जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है; और
ii. समिति का **136वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा)जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति का **57वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्याः 2) के पैरा संख्याः3.3 की संवीक्षा पर आधारित है तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं ।

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

18/03/2016/1200/RG/AG/5

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति के **29वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 9वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

एम.एस. द्वारा अगली मद शुरू

18/03/2016/1205/MS/AG/1

<u>नियम -62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। अब डॉ0 राजीव सैजल जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

डॉ0 राजीव सैजलः अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 16 मार्च, 2016 को "अमर उजाला" तथा "हिमाचल दस्तक" नामक समाचार पत्रों में छपे समाचार शीर्षक "सरकारी दाल के पैकेट में निकला मरा हुआ चूहा" से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
अध्यक्ष जी, हमें भी यह बात समाचार पत्रों के माध्यम से पता चली कि मेरे क्षेत्र में धर्मपुर स्थित एक डिपो से 10 मार्च को एक महिला डिपो से राशन लेने गई थी। जब वह महिला राशन लेकर घर वापिस आई और उसने जब वह मसूर की दाल का पैकेट खोला तो उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। उस पैकेट को खंगालने पर उसमें उसने एक मरा हुआ चूहा

देखा। अध्यक्ष जी, यह स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। अध्यक्ष जी, जो एक गरीब व्यक्ति डिपो से राशन लेता है और उसके साथ यदि ऐसा हो जाए तो यह उन गरीबों के साथ खिलवाड़ है। दूसरे, बहुत सी बीमारियों का वाहक भी चूहा होता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तीसरे, जिसने यह घटिया राशन विभाग को सप्लाई किया है यह उसकी भी बहुत बड़ी लापरवाही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि मसूर की दाल का यह पूरा-का-पूरा लॉट जिसमें से यह मरा हुआ चूहा निकला है, वापिस मंगवाया जाए क्योंकि यह दाल पैकेट में तो बाद में भरी गई होगी जबकि उस पूरे लॉट में ही वह मरा हुआ चूहा होगा। बल्कि मरे हुए और भी चूहे हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिसने भी यह दाल सप्लाई की है और साथ में मरा हुआ चूहा सप्लाई किया है, उस ठेकेदार के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा क्या आप विभाग को भी चुस्त-दुरुस्त करेंगे क्योंकि विभाग की भी यह बहुत बड़ी लापरहवाही है। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पुनः गुजारिश करना चाहता हूं कि मसूर की दाल के इस पूरे-के-पूरे लॉट को आप वापिस मंगवाएं ताकि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस दाल के खाने से लोगों को न हो।

18/03/2016/1205/MS/AG/2

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदस्य डॉ0 राजीव सैजल द्वारा उठाए गए मामले पर जोकि दिनांक 18-3-2016 को निर्धारित हुआ है पर मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, डॉ0 राजीव सैजल, माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा नियम-62 के अन्तर्गत ''धर्मपुर के समीप कण्डा डिपो से आबंटित की गई मसूर की दाल के पैकेट में से मरे हुए चूहे के मिलने से उत्पन्न स्थिति'' बारे मामला इस मान्य सदन के समक्ष उठाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूँ कि "अमर उजाला" समाचार पत्र के दिनांक 16-03-2016 के अंक में **''सरकारी दाल के पैकेट में निकला मरा हुआ चूहा'' शीर्षक** से समाचार प्रकाशित हुआ है व अन्य समाचार पत्रों में भी इस बारे समाचार प्रकाशित हुआ है । इस मामले की प्रारंभिक जांच दिनांक 16-03-2016 को हि0प्र0 खाद्य आपूर्ति निगम सीमित के क्षेत्रीय प्रबन्धक से करवाई गई है व यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्रीमति सीमा भारद्वाज नामक उपभोक्ता को जिला सोलन की उचित मूल्य की दुकान दि कण्डा कृषि सेवा सहकारी सभा, धर्मपुर से दिनांक 10-03-2016 को एक किलो दाल मसूर का पैकेट जारी किया गया था व यह पैकेट जारी करते समय दाल के पैकेट में कोई कमी नजर नहीं आई थी । उक्त उचित मूल्य कीदुकान को यह दाल निगम के थोक गोदाम, धर्मपुर से दिनांक 20 फरवरी, 2016 को जारी की गई थी। इस मामले में निरीक्षक,खाद्य, नागरिक उपभोक्ता मामले, धर्मपुर द्वारा जांच की गई है व दाल मसूर के इस सीलबंद पैकेट में मरा हुआ चूहा पाया गया है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

18.03.2016/1210/जेएस/एएस/1

खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले मंत्रीः-------जारी.....

यह पैकेट जिला नियंत्रक, सोलन द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को भेजा गया है व प्रयोगशाला में विश्लेषण के दौरान ये सैम्पल Unfit for human consumption पाया गया जिसके बारे में आवश्यक report हि0प्र0 खाद्य आपूर्ति निगम सीमित को भेजी गई।

इस दाल की आपूर्ति मै0 जिंदल सुपर दाल मिल, दिल्ली से बिल न0 84400 दिनांक 25-01-2016 द्वारा निगम के थोक गोदाम, धर्मपुर को की गई है । इस पार्टी द्वारा माह दिसम्बर, 2015 से इस दाल की आपूर्ति की जा रही है तथा अभी तक लगभग 20 लाख पैकेटों की आपूर्ति की जा चुकी है। अभी तक किए गए नमूनों के विश्लेषण में वर्तमान मामले

को छोडकर कोई भी इस तरह का अन्य मामला प्रकाश में नही आया है। चूंकि यह एक गम्भीर मामला है तथा आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

इस समाचार के संज्ञान में आने के बाद सुपर दाल मिल, दिल्ली को पत्र संख्याःएचपीएससीएससी/प्रो0/4-2/2015(I)-न्यूजआईटम-40308 दिनांक 16-03-2016 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सोलन को दिनांक 16-03-2016 को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस कन्साईन्मैन्ट से सम्बन्धित बिना बिकी हुई मात्रा को उचित मूल्य की दुकानों को जारी न किया जाए व यदि उचित मूल्य की दुकानों पर इस कन्साईन्मैन्ट में से जारी की गई मात्रा में से यदि कोई स्टॉक उनके पास बिना बिके प़डा है तो उसे तुरन्त वापिस उठाया जाए व आपूर्तिकर्ता को वापिस किया जाए। इस मामले में आपूर्तिकर्ता से निविदा की शर्तो अनुसार सम्बन्धित कन्साईन्मैन्ट के मूल्य की 20 प्रतिशत राशि की दण्डस्वररूप कटौती व बिना बिके हुए स्टॉक को बदलवाने बारे कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके साथ मैं एक बात और शामिल करता हूं कि अगर इस कन्साईनमैंट की सप्लाई घर पर भी है तो वे वापिस करें अगर वह human consumption के अनफिट है तो उसको हम वापिस करेंगे।

महोदय, मैं इस सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जा रहे विभिन्न खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है तथा इस मामले में भी दोषियों के विरुद्ध क़डी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ।

18.03.2016/1210/जेएस/एएस/2

अध्यक्ष महोदय, माननीय धूमल साहब ने जब यह मामला उठाया था हमने तकरीबन 500 सैम्पल्ज़ और एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में कमेटियां बना करके पुरे प्रदेश से उठाए हैं। सैम्पल टैस्टिंग में गए हुए हैं। अभी 65 सैम्पल्ज जो हुए हैं उनमें से 2 सैम्पल्ज़ फेल हुए हैं बाकी उनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 20 लाख पैकेट आए हुए हैं उसमें जैसे-जैसे लेबोरेटरी के रिजल्ट आते जाएंगे अगर गलत पाए गए तो जो टेण्डर कंडिशन है उसके मुताबिक उनको दण्ड दिया जाएगा।

18.03.2016/1210/जेएस/एएस/3

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान

सामान्य चर्चा का समापनः

अध्यक्षः वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा दिनांक 14. 3. 2016 को आरम्भ हुई थी, इसमें कुल 45 सदस्यों ने भाग लिया और चर्चा 18 घंटे 51 मिनट्स तक चलती रही। अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

Chief Minister: Mr. Speaker Sir, as you have stated just now 45, Hon'ble Members have participated in the budget discussion from 14th to 17th March, 2016. The discussion on the Budget was held in a very cordial atmosphere. The participation of such a large number of Members in the Budget discussion itself shows that the budget 2016-17 has enthused the members, as it has many new policies and programmes, benefitting all sections of the society. People of Himachal Pradesh and Members from the Treasury Benches have immensely appreciated the budget. However, a feeble criticism has come from opposition benches. Now, I will reply, one by one, on the important issues raised by the Hon'ble Members;

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

18/3/2016/1215/SS/AS/1

Chief Minister continue

If I have to reply to each and every issue, it will take lot of time. But I have tried to first focus on the important points and if any question is raised after I finish my speech, I will prepare to reply to that also.

Sir, Hon'ble Shri Prem Kumar Dhumal, Shri Rajeev Bindal, Shri Hans Raj, Shri Suresh Bhardwaj, Shri Virender Kanwar, Shri Bikram Singh, Shri Ravinder Singh, have raised the issue that Per capita debt is Rs. 47,284 in Himachal Pradesh and debt-GSDP ratio is 39 percent in the State whereas it is 21 percent at the Centre level. Over the past years the State has also failed to generate extra revenue. Mr. Speaker, Sir, I would like to state that high level of debt during the recent years is mainly because of sharp reduction in revenue deficit grant by the 13th Finance Commission, during the years 2013-2014 and 2014-2015, coupled with the increased salary burden due pay scale revision by the Punjab Government and followed by the H.P. Government. The Revenue Deficit Grant which was Rs. 2232 come for the first year i.e. for 2010 and 2011 on the award was reduced sharply to Rs. 406 crores in the last year i.e. 2014-2015 of the award of the 13th Finance Commission period. Moreover, there was over estimations in the recommendations of the 13th Finance Commission on account of share in Central Taxes, for the year 2013-2014 and 2014 and 2015. Actual receipt during the 2 years was less by Rs. 528 crores, compare to the amount estimated by the 13 Finance Commission.

1215/18/3/2016/SS/AS/2

Despite limited resources, the State Government has succeeded in bringing down debt GSDP ratio to 34.8% during the year 2014 and 2015, as against the target of 40% fixed by the 13th Finance Commission. Further the State Government has raised all the market loans only after the obtaining approval of the Government of India. Under the Article 239 (3) of the Constitution of India.

We are aware that increasing debt liability is a matter of concern which requires special attention. Speaker Sir, Himachal Pradesh has very low tax

base. However, the State Government has been making efforts to increase the tax revenue through efficient tax collection.

...continue in English by DC

18.03.2016/1220/KS/DC/1

Chief Minister Continues……..

The tax revenue of the State Government from its own resources was Rs. 4,626 crore in 2012-13 which has increased to Rs. 6,341 crore in 2015-16 and is likely to increase to Rs.7,469 crore during 2016-17. We will also take steps to contain the debt in future by better resource mobilization and prudent expenditure. Sh. Prem Kumar Dhumal has raised the issue that the Officers have misled the Hon'ble Chief Minister regarding reduction in entertainment duty which was reduced to 10 percent in 2012, hence, there is no new case of reducing entertainment duty on ropeway and cinema halls. Speaker Sir, the Leader Of Opposition has not gone through the para-97 of my Budget Speech in the right perspective. I have clearly announced that the entertainment duty on various entertainments was reduced from 100 percent to 10 percent in year 2012. However, the entertainment duty on Ropeways continues to be 25 percent and on cinema hall at 20 percent. I would like to inform the August House that there were different rates of Duties under the Himachal Pradesh Entertainment Duty Act, 1968. The entertainment duty has been reduced from 100 percent to 10 percent in the year 2012 on such entertainment where the duty was applicable at the rate of 100 percent. However, the State Government also imposed 25 percent duty on the aerial Ropeways,
vide notification dated 17th February, 2000 and imposed 20 percent duty on Cinema Halls vide the State Government notification dated 8th August, 2003. Now, in this budget, I have announced that these duties will also be brought

down to 10 percent to promote these activities. I have further announced that new Cinema Halls will be exempted from entertainment duty for five years. Hon'ble Speaker Sir, Sh. Prem Kumar Dhumal, Sh. Thakur Gulab Singh, Sh. Jai Ram Thakur, Sh. Rajiv Saizal, Col. Inder Singh, Sh. Suresh Bhardwaj, Sh. Ravinder Singh have raised the issue that the State

18.03.2016/1220/KS/DC/2

Government has The State Government has received total grant of Rs. 21,691 crore on the recommendations of the 13th FC whereas the 14th FC has increased the Revenue Deficit Grant (RDG), Grant to Panchayats and under SDRF substantially. However, nobody is extending thanks to the Centre for this increase. Speaker Sir, the 13th FC had grossly under estimated the committed liabilities of the State. While the commission recommended an average increase of 126 percent to other States compared to 12th FC, the increase in case of Himachal Pradesh was only 50 percent, which was the lowest in the Country. Speaker Sir, we pursued our case with the 14th FC in the right spirit. Consequently, the 14th FC has given us a reasonable increase in the award. I have already
thanked the 14th FC for accepting the State Government Memorandum and demand. Further, I have thanked the Government of India and NITI Aayog in para 12 of my Budget Speech for providing funds under CSS on 90:10 ratio. However, the closure of the Planning Commission has resulted in the loss of Rs. 3,000 crore per annum of the Central Plan Assistance which has adversely affected the finances of the State. In fact closing of the Finance Commission has proved to be a desuster so far the small states are concerned. I also want to inform that the NITI Aayog is not providing any money to fund the State Plan.

Continued by DC…

18.03.2016/1225/AV/DC/1

Chief Minister Continues…..

Speaker Sir,Sh. Prem Kumar Dhumal, Sh. Rikhi Ram Kondal, Sh. Jai Ram Thakur, Col. Inder Singh, Sh. Suresh Bhardwaj, Sh. Govind Ram Sharma has raised the issue regarding the medical claims of the pensioners are pending. Speaker Sir, the State Government is very much concerned about the timely release of medical claims of the pensioners. For the year 2016-17 a provision of Rs. 59 crore has been made for this purpose by giving an increase of 12 percent over the budget estimates of 2015-16. There is no pending case for medical reimbursement of pensioners with the Finance Department. Further, I assure this August House that additional funds will be provided for Medical Reimbursement of Pensioners, as and when required.

Sh. Prem Kumar Dhumal, Thakur Gulab Singh, Sh. Jai Ram Thakur, Col. Inder Singh, Smt. Asha Kumari, Sh. Virender Kanwar, Sh. B.K.Chauhan have raised the issue that electric fencing of farms, whether vetted from the Law Department or not ? Whether it is safe for human beings and animals?

Speaker Sir, few of the Hon'ble members have shown concern about the safety aspects of the power fencing. I wish to inform the members, that the NABARD has formulated a scheme for solar power fencing of farms which has been examined by the Department of Agriculture. The University of Horticulture and Forestry has also installed the solar power fencing on pilot basis. I have the book here which gives details about the power fencing, which is issued by Rashtriya Krishi And Gramin Vikas Bank after study. Right now I have one copy only, we will

18.03.2016/1225/AV/DC/2

send you the copies. It shows that the power fencing which depends on the solar power is absolutely safe.

Continued by AG……

18032016/1230/AG-TCV/1

Chief Minister Continues . . .

It only gives a shock. It doesn't go beyond giving shocks. So, this is the safe way. It is in vogue. It is in practice in many places. It has been proved successful. I am sure this will be the safe way of keeping the unwanted guests from the fields, whether human or others.

As I was saying that the University of Agriculture and Forestry has also installed the solar power fencing on pilot basis. Ever since the experimental farm was fenced by the University, not a single money has been sighted in the area.

Therefore, to control crop damages by the wild animals, solar/electric power fencing appears to be an effective alternative. Current in the fence around the farms will be sufficient to keep away the wild animals and monkeys from the farms. The electric shock in the fence will not be fatal for animal or human being. The detailed guidelines will be issued separately by the Agriculture Department. I assure this House that certification of safety features of the equipments which will regulate the electric current will be ensured.

Prof. Prem Kumar Dhumal has also raised an issue that Mukhya Mantri Universal Health Protection Insurance Scheme was already launched in 2010.

Speaker, Sir, I would like to inform this August House that the UPA Government launched the "Rashtriya Swasthya Bima Yojna". The then Government at the State level only adopted that Scheme in 2010. There was no State scheme for health insurance at that time. In the Budget Speech of 2015-2016, I launched Mukhya Mantri State Health Scheme for treatment of both basic and critical ailments for the Ekal Nari and senior citizens above eighty years of age, irrespective of income level. This was fully funded by the State

Government. Now, in the present Budget, I have announced the "Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme"

18032016/1230/AG-TCV/2

for all persons in the State, who are not covered under other schemes to extend the benefit of Health Protection to every section of the society. So, there is a difference between the two.

Once again, Prof. Prem Kumar Dhumal has also raised the issue that investment meets and flow of investments, closure of Malwa Cotton and disconnection of power connection of 63 units in Parwanoo.

Contd. By AG in English . . .

18.03.2016/1235/AG-RKS/1

Chief Minister Continues . . .

Speaker, Sir, the State Government has been successful in attracting new industrial investment in the last three years. We organise investment meets in Mumbai, Bangluru, Ahmedabad and also New Delhi and since these meets we received 41 new proposals and 60 projects for expansion involving investment of Rs. 4,070 crores.

As far as M/s Malwa Cotton is concerned, it was established in the year 1989 and has closed down. The primary reasons for closure of this unit are market competition, debt burden and obsolete technology.

In Parwanoo, out of 63 units, 13 units were provisionally registered, five units shifted to Baddi. They were at Parwanoo and shifted to Baddi. And the rest of the industrial units were not of substantial nature and had very small investment. Similarly, in Kala Amb, out of 29 units, where power connections

were disconnected, seven units were not permanently registered, 11 units have disconnected their power temporarily.

Speaker, Sir, in 2012-2013, the power consumption by the industrial units in the State was 4,491 million units which has increased to 4,758 million units in 2015-2016. These figures prove that the existing industry is doing well despite the overall adverse economic scenario in the country.

In order to increase industrial investment in the State, my Government has initiated various measures by providing incentives of electricity duty, CST, VAT, Entry Tax, CLU charges, reduction in stamp duty, relaxation in floor area ratio etc. and various measures have been taken for ease of doing business. In addition to this, I have announced that following measures in the present Budget to retain and encourage new investment;

1. Traders upto turn over of Rs. 30 lacs covered under the lump sum tax payment scheme;

18032016/1235/AG-RKS/2

2. The dealers upto turn over of Rs. 1.50 crores covered under the deemed assessment;
3. Entry Tax on input/raw material for existing industries reduced from 2 per cent to one per cent and for the new industry reduced from 1 per cent to half per cent.
4. Such existing industry which undertakes substantial expansion will be given benefit of reduced electricity duty and CST at par with new industry.

To encourage the new enterprises in the State, following measures have been proposed:

1. All the new enterprises in the State to submit only self certified documents online or manually.

2. Registration within fifteen days from submission of documents.
3. land will be provided at concessional rates in the industrial areas . . . . .

Continued by DC in English . . .

18.3.16/1240/SLS/AS/1

Continue…..Chief Minister

4. Stamp duty on registration of land for new Industry will be charged at 3 percent only.
5. 25 percent reduction in the fees for Green Industry and 10 percent reduction in Orange Industry for consent to establish or for renewal.
6. Interest subvention at the rate of 4 percent upto a loan of Rs. 10 lakh for three years.

Speaker Sir, the representatives of the Industries have applauded these measures and will definitely boost industrial investment in the State. Shri Prem Kumar Dhumal, Shri Jai Ram Thakur, Shri Vinod Kumar, Col. Inder Singh, Shri Govind Ram Sharma, Shri B.K.Chauhan, Shri Baldev Tomar have raised some issues that during last Budget speech the Government had promised that in view of increased monkey menace it will take steps for sterilizing monkeys and declaring the monkeys, vermin, so that farmers can effectively deal with the problem. The government is conscious of the problems caused by monkeys and other wild animals to the crops and people of the State. We have carried out the task of monkey sterilization with greater degree of effectiveness. From the year 2012-13, 54,880 monkeys have been sterilized till date. Further, in 348 forest beats the problem is very serious. For these beats, we have taken up with Government of India for declaring monkeys, vermin, as per provisions contained in "Wild Life Protection Act, 1972". Once these are declared vermin

the provisions of the "Wild Life Protection Act, 1972" will cease to apply to them.

18.3.16/1240/SLS/AS/2

Shri Prem Kumar Dhumal, Sh. Krishan Lal Thakur has raised the issues and asked that how many houses were sanctioned and have actually been constructed under various housing schemes?

From the year 2012-13 till date, a total of 30,700 houses have been sanctioned under different housing schemes. Out of these, 20,849 houses have been completed and remaining 9,851 houses are under construction.

Shri Prem Kumar Dhumal has raised the issue regarding payment of extra Rs. 36 over and above the tendered price for procurement of LED Bulbs.

Speaker Sir, Hon'ble Prime Minister of India has launched a national programme for LED based energy efficiency. M/s Energy Efficiency Services Limited (EESL) which is a Government of India Undertaking is implementing this programme, in all the States including Himachal Pradesh. The LED Bulbs are distributed in the State of HP at the rate of Rs. 100 per bulb on cash payment and at the rate of Rs.105 on equated monthly installments. The procurement of LED bulbs is being done by EESL i.e. is a public sector company of the Central Government and HPSEBL is supporting it in its distribution. ……interruption……Please let me finish..interruption… I don't need.

Interruption…… Let me finish this point then you say.

..continue by RG

18/03/2016/1245/RG/AS/1

मुख्य मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात.....

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस बात को ये कह रहे हैं--(व्यवधान)----यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है।--(व्यवधान)----

अध्यक्ष : महेन्द्र सिंह जी, आप पहले मुख्य मंत्री जी को उत्तर तो देने दीजिए।--(व्यवधान)---

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्वैच्छिक स्कीम है। कल भी हमारा यही आरोप था कि एल.ई.डी. बल्ब के वितरण में आपने तीन पार्टनर्ज बना लिए, तीन कम्पनियों को जोड़ लिया।--(व्यवधान)----इस प्रदेश के 19,66,000 लोगों को ये दिए गए। 60/- या 62/- रुपये में मिलने वाला बल्ब इतना महंगा बेचा जा रहा है।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, माननीय मुख्य मंत्री जी उसी का जवाब दे रहे हैं, आप इस तरह बीच में नहीं बोल सकते।--(व्यवधान)---- आप बैठ जाइए।--(व्यवधान)----You can't do like this. This is the wrong procedure. कृपया, आप बैठ जाएं।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए।--(व्यवधान)----

Speaker You can't speak within the reply. --(व्यवधान)----

Chief Minister Alright, sit down please. Your point is irrelevant. You are ill informed. आपको पता कुछ भी नहीं है। सदन में खड़े होकर जो मर्जी कह दो। We have heard you, now hear my reply.

Speaker : Hear the reply of the Hon'ble Chief Minsiter then you can ask for clarification. आप बाद में स्पष्टीकरण मांग लीजिए, लेकिन पहले मुख्य मंत्री महोदय को जवाब तो देने दीजिए। Let him read--(व्यवधान)----जब ये बोल रहे हैं, तो आप चुप रहिए। बाद में स्पष्टीकरण मांग लें, अभी आपने क्या बोलना है? --(व्यवधान)----पहले

इनको बोलने दीजिए। this is wrong-(व्यवधान)---- आप इसके बाद स्पष्टीकरण मांग लेना। I will give you time after that.

18/03/2016/1245/RG/AS/2

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ कहने की कोशिश करने लगे।)

Chief Minister : Sir, as I have stated earlier that the pooled rate of the bulb is Rs. 78 and Rs. 22 are charged by the EESL for Entry Tax, Service Tax, Handling charges etc. In India, 7 crore LED bulbs have been distributed and in Himachal Pradesh 51 lakh bulbs have been distributed to the consumers willing to take the LED bulbs.

(विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ड्रामा कब तक चलेगा? ये जो मर्जी कहें, जब सरकार इसका जवाब देती है जो तथ्यों पर आधारित है और ये जो एल.ई.डी. बल्ब हैं, इनको भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा सप्लाई किया गया है।

एम.एस. द्वारा जारी

18/03/2016/1250/MS/DC/1

मुख्य मंत्री जारी----

भारत सरकार के उपक्रम ने इसकी कीमत 78/-रुपये प्रति बल्ब निर्धारित की है और उसके ऊपर 22/-रुपये ई0ई0एस0एल0 चार्ज करता है for entry tax, service tax and handling tax etc. In India, 7 crore LED bulbs have been distributed and in HP 51

lakh bulbs have been distributed to the consumers willing to take the LED bulbs. It is not compulsory, anybody who wants to take it, can take it. HPSEB is only making it available to the people at the price fixed by the EESL. Sir, the walk out is against the Government of India in this case. यह स्कीम भारत सरकार की है और भारत सरकार की कम्पनी इन बल्ब्स को सप्लाई करती है। इसकी कीमत उन्होंने निर्धारित की है। इसलिए अगर ये वॉक आउट कर रहे हैं तो the walk out is not against this Government they are walking out against the Centre Government. Actually Mr. Prem Kumar Dhumal has become a prisoner in hands of some of his colleagues. It is not he, who leads them , it is they who are leading him. It is very sorry state of affairs. And in regard LED bulbs it is voluntary , it's not compulsion जो बल्ब लेना चाहते हैं वे लें, जो नहीं लेना चाहते मत लें। अध्यक्ष जी, मैं जानता था कि मेरे भाषण के दौरान ये लोग जरूर बाहर जाएंगे लेकिन इन्होंने बहुत ही कमजोर प्वाइंट बाहर जाने के लिए ढूंढा। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सुबह से ही वॉक आउट करने का फैसला करके आए थे। परन्तु यदि ये किसी कन्ट्रोवर्शियल मैटर पर बाहर जाते तो अच्छा होता। यह वॉक आउट जैसा मैं कह रहा हूं this walkout is against the "Modi Government "not against "Virbhadra Singh Government".

18/03/2016/1250/MS/DC/2

Speaker: Actually, I asked them to seek their interrogation after the Hon'ble Chief Minister will finish his address. But they were adamant and they were raising their interrogation between the reply, which would have been made after reading the answer. This is unfortunate that these Members have walked out, it is against the Rules.

Chief Minister: They are discouraging the House. Walking out after participating in the Budget speech and discussion on the Budget, it is only fair

that they sit down and listen to the reply also. In fact their walkout shows dis respect to the House.

Speaker: More over we have given them time to seek for clarification after you read out, but they didn't wait for that. They were in mood to go out.

Chief Minister: Speaker Sir, now if they want to go to their standards, I cannot stop them, and this shows how disheartened they are. The recent stounding and stunning victory of the Congress party in the recent Panchayat elections has demoralized them. Now they don't want to hear the truth.

Continued by DC…

18/03/2016/1255/JS/DC/1

Continued by Chief Minister:-

Shri Prem Kumar Dhumal and Smt. Asha Kumari has raised the issue regarding construction of parking and children parks. With the increase in number of vehicles on road, the congestion and traffic jams have increased. It has necessitated the construction of parkings. Addressing this issue, during the last three years 15 car parkings have been completed in different Municipalities and the work is in progress in 9 Municipalities. Further the work at four parking sites is in full swing on PPP mode under Municipal Corporation, Shimla. In the year 2015-16 the State Government allocated a budget of Rs. 15 crore for the construction of parking under matching grant of 50:50 scheme. Out of this Rs. 12 crore stands released and the proposal of Rs. 3 crore is under process. For good health and a decent living standard, the children and common people need parks and open spaces. Recognising, this I have proposed allocation of a sum of Rs. 10 crore for development of children parks for the first time in 2016-17. These parks will be developed on 50:50 fund

sharing between the State Government and the concerned urban body. Further, a budget provision of Rs. 4.50 crore has been earmarked for Municipal Corporation Shimla for park, road etc.

Sh. Prem Kumar Dhumal, Sh. Suresh Bhardwaj and Sh. Bikram Singh Jaryal raised the issue that RUSA has created problems for the students and students from the HPU are being denied admissions in different institutions. Speaker Sir, RUSA has been started in the year 2013 as per the guidelines issued by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. On the direction of University Grants Commission, the Himachal Pradesh University has started Credit Based Choice System (CBCS). The Universities which are not following CBCS system might have expressed some reservations regarding admissions of students on the basis of CBCS scores. The HPU

18/03/2016/1255/JS/DC/2

being sensitive to this genuine concern, has taken up the matter with Ministry of Human Resource Development, Government of India and University Grant Commission for issuing a clarification in this regard. We will pursue this matter, so that the students do not face any inconvenience.

Sh. Prem Kumar Dhumal, Sh. Narinder Thakur, Col. Inder Singh, Sh. Ravinder Singh and Sh. Virender Kanwar who are unfortunately not present in the House , never the less I feel I must reply to the points raise by them. They have raised the issue that the contribution of Agriculture and Allied Services Sector in the GSDP has come down considerably which is worrisome. Speaker Sir, it has been empirically established that as the economy grows the structural changes within the economy occur in such a way that the share of service sector and secondary sector increases in the GSDP and the share of Agriculture Sector declines. The most developed nations in the world have very small contribution of Agriculture Sector in their GDP.

Continued by AG….

18032016/1300/SS-AG/1

Chief Minister Continues . . .

The Agriculture Sector in USA contributes only 1.2 per cent to its GDP; 0.7 per cent in United Kingdom; and 1.3 per cent of the total GDP is contributed by the Agriculture Sector in Switzerland. At the national level also the Agriculture Sector contributes 11.9 per cent to the GDP. Going by the standards the declining share of Agriculture Sector in GDP is the sure sign of development in Himachal Pradesh. However, my Government is committed to enhance the Agricultural productivity and this is being attempted by enhancing the budget outlays for Agriculture and allied services sector on yearly basis.
The Plan outlays for Agriculture and Allied Services Sector in 2012-13 were Rs. 466 crore which has increased to Rs. 712 crore in 2016-17.

Prof. Prem Kumar Dhumal, Shri Rajiv Saizal and Col. Inder Singh raised the issue regarding the electricity production in the State has come down during 2014-15 as compared to 2013-14.

Speaker Sir, the Leader of Opposition mentioned the figure contained in the Economic Survey for the year 2014-15. The survey mentioned the power generated only by the Himachal Pradesh State Electricity Board, which has come down due to shutting down of Bhaba Hydel Project as a result of a calamity. If power generation by all the agencies in the State which provide free power to the State Government is taken into account, the power production has increased from 20,105 Million Units in 2012-13 to 22,491 Million Units in 2013-14 and further to 24,617 Million Units in 2014-15. The generation during 2015-16 up to the month of December, 2015 is 26,311 Million Units. Hence, the power production in the State is continuously increasing.

Prof. Prem Kumar Dhumal, Shri Vinod Kumar and Shri B.K. Chauhan raised the issue regarding enhancement by one rupee in the milk

18032016/1300/SS-AG/2

procurement prices is inadequate considering the high market price of milk per litre.

Speaker Sir, the procurement rate per litre of milk was Rs. 17.80 in 2012-13 which was increased to Rs. 18.80 in 2013-14, was further enhanced to Rs. 19.80 during 2014-15, and to Rs. 20.80 during 2015-16. Now it has been proposed to be increased to Rs. 21.80 per litre during 2016-17. These regular increases in the purchase price of the milk are benefiting lakhs of milk producers in the State.

Prof. Prem Kumar Dhumal raised the issue that the total cost of Himachal Pradesh Forest Eco System Climate Proofing Project was shown as Rs. 310 crore in the Budget Speech for the year 2015-16 whereas the cost has been reduced to Rs. 240 crore in the Budget Speech for the year 2016-17.

Contd. By AG in English . . .

18032016/1305/KS-AG/1

Chief Minister Continues . . .

Speaker Sir, the KFW Bank of Republic of Germany is to provide 30 Million Euros of concessional loan. This amount when converted into rupees comes out to be around Rs. 246 crore at the current exchange rate between Indian Rupee and Euro. Apart from this loan KFW Bank providing Rs. 16.4 crore as grant. The State Government will be providing Rs. 35 crore as its own

share and the beneficiaries will be contributing their share amounting to about Rs. 12 crore. When all these amounts are added up, the total costs of the project comes out to Rs. 311 crore. Hence both the figures are correct, the total project is of Rs. 311 crore and KFW is to provide Rs. 246 crore.

Prof. Prem Kumar Dhumal, Shri Mahender Singh and Shri Jai Ram Thakur raised the issue that the actual subsidy on the anti-hail nets is not 80 per cent but is only 30 per cent and the remaining 50 per cent subsidy is being given by the Government of India.

The benefit of the scheme of providing anti-hail nets was made available only to a few people.

Speaker Sir, in my Budget Speech for the year 2014-15, I had announced enhancement of subsidy on anti-hail nets to 80 per cent but it was never claimed that the subsidy would entirely be met by the State Government. The intention of my Government was to enable even the poor farmers to use anti-hail nets by providing additional subsidy of 30 per cent out of the State exchequer in addition to 50 percent already being provided by the Government of India.

Speaker Sir, believing in the principle of inclusive development, the benefits of the scheme have not been confined to a particular area rather the benefits of the scheme have been made available to all the apple producing areas of the State. A total area of 34 lakh square meters have

18032016/1305/KS-AG/2

been covered under the scheme of providing anti-hail net, in last three years.

Prof. Prem Kumar Dhumal raised the issue that Ropeways from Dharamshala to McLeodganj, Toba to Naina Devi Ji, Himani to Chamunda Ji, Dharamkot to Bhagshunag-Triund, ShahTalai to Deotsidh and Tourist Information Centre at

Bye Pass, Lift and Mall Road were announced during the Budget Speeches of previous years. However, no progress has been made so far.

Continued by DC in English . . .

18.3.16/1310/AV/AS/1

Chief Minister continue……

Speaker Sir, I wish to share with the August House that the work on the Ropeways from Tourist Information Centre – Bye Pass- Lift-Mall Road; Himani to Chamunda Ji; and, Dharamshala to Mc-Leodganj have already been awarded and the concession agreement on these three rope-ways have already been signed in, 2015. The bidding process for execution of Rope Ways from Toba to Naina Devi Ji, Dharamkot to Bhagshunag-Triund and ShahTalai to Deotsidh are under process.

One Hon'be Member of the Opposition raise the issue distribution of 5,000 Lap-Tops/ Net-Books to the meritorious students was announced during 2012-13, distribution of 7,500 Lap-Tops/Net Books were announced during 2013-14 and distribution of 10,000 Lap-Tops and Net-Books was announced during 2015-16. However, actual numbers of Lap-Tops/Net-Books distributed is much less.

Speaker, Sir, 5,000 Net-Books were distributed against the target of 5,000 in the year 2013-14 and 7,500 Lap-Tops as announced during 2014-15 also stands distributed. The Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation is already in the process of procuring 10,000 Lap-Tops for distribution as announced during the budget speech of 2015-16. Shri Suresh Bhardwaj has raised the issue of old specifications of Laptops being procured. I wish to inform the house that laptops of the latest specifications are being procured by the HPSEDC.

Shri Prem Kumar Dhumal, Shri Hans Raj, Shri Bikram Singh Jarayal, Shri Narinder Thakur, Thakur Gulab Singh, Shri Jai Ram Thakur, Shri Rikhi Ram Kondal, Sh. Rajiv Saizal, Col. Inder Singh, Shri Vinod Kumar, Shri Bikram Singh that the new Educational Institutions are being opened which has resulted in deterioration of quality education.

18.3.16/1310/AV/AS/2

Mr. Speaker, Sir, The educational institutions are being opened and up-graded by my Government on the basis of the demand of the people. It is my Government's priority to ensure easy and universal access to education. To cope with the shortage of staff in the educational institutions, my Government has started a recruitment drive in 2013-14 which still continues. During the last three years thousands of posts in the Education Department have been filled-up. More than 5,000 teaching posts in the Education Department are proposed to be filled-up during 2016-17. I can assure you, Sir, that we are very much concerned about it. We will give top priority to fill the vacant posts of teachers at all levels. Because without teachers education system cannot be successfully implemented.

...continued by AS

18.3.16/1315/TCV/AS/1

Chief Minister continue.....

My Government has taken several steps to improve the quality of education in the Government schools of the State. English, Hindi and Maths will be taught from class-1. The text books for classes 1st to 5th have been revised as per the National curriculum. Speaker Sir, with the very objective of improving the quality of education, my budget speech for the year 2016-17 proposes starting

of Mukhya Mantri Shikshak Samman Yojana, Mukhya Mantri Adarsh Vidyalaya Yojana and Mukhya Mantri Gyan Deep Yojana.

Shri Prem Kumar Dhumal raised the issue Establishment of War Memorial Museum at Dharamshala was announced during 2014-15, however, no progress has been made in its execution.

Speaker Sir, the map of the proposed Museum has already been approved and the concurrence has been conveyed to office of the Chief Architect. A budgetary provision of Rs. 5 crore has been kept during the financial year 2016-17 for this Museum. Execution of the project will be ensured at the earliest and additional requirement of funds depending on the pace of execution of the work will also be provided. I would like to addmany Hon'ble Members of this House have also contributed for construction of this Museum and so far speed is concerned, I have directed the Department that this work should be completed within this financial year and whether we have to work in two shifts but it will be completed this year.

Speaker Sir, the Congress Party takes pride in sharing with this August House that a sum of Rs. 87 lakh has been contributed by the MLAs of the ruling Congress Party for construction of this museum.

18.3.16/1315/TCV/AS/2

Shri Mahender Singh, Sh. Baldev Singh Tomar raised the issue that there has been there has been a discrimination in allocating the funds to different zones of the Public Works Department and Irrigation & Public Health Department during 2016-17.

Speaker Sir, the Zone wise and Circle wise allocation of budgeted funds is made by taking into consideration the factors like the total area, population served by a Zone or a Circle; number of ongoing schemes, the stage of their progress in each Zone or Circle; and, the new schemes proposed to be started during a financial year. No discrimination is ever exercised while allocating the budgeted outlays to Zones and Circles as the budgetary outlays are finalized with the consideration of development of the State as a unit.

Speaker Sir, I wish to share with the members of the opposition that it is the Kangra/Dharamshala zone for which maximum allocations, have been proposed for the year 2016-17 based on the criteria mentioned above, both under Public Works and Irrigation and Public Health Departments and not for Shimla zone, as is being alleged.

..continue by Smt. DC

18.03.2016/1320/RKS/DC/1

मुख्य मंत्री .... जारी.....

जो मुहं में आता है, बोल देते हैं। I don't think most of them have read the budget and by the here say they get up here and start saying. The Annual Plan size for the year 2016-17 should have been at Rs. 9,800 crore to reach the approved size of Rs. 22,800 crore for the 12th Five Year Plan. The plan expenditure during first three years of the 12th Five Year Plan (2012-17) has been Rs. 12,685 crore. The Plan expenditure during 2015-16 is expected to be Rs. 5,100 crore. Hence, the total Plan expenditure during the entire 12th Plan period will be more than Rs. 22,800 crore . Speaker Sir, earlier the release of the Central Plan Assistance was dependent on the level of Plan expenditure reached during a financial year, in the planning Commission era. However, with the closure of Planning Commission, no Central Plan Assistance is being provided by either the NITI Aayog or Government of India.

Sh. Mahender Singh raised the issue that the Backward Area funds are being utilized in Non-Backward Areas. Speaker Sir, Backward Area Sub Plan funds are utilized only for the development works executed in the declared backward areas of the State. As per the policy guidelines to implement Backward Area Sub Plan, these funds cannot be diverted to no-backward areas. The allocation under Backward Area Sub Plan in the year 2012-13 was Rs. 35 crore was increased to Rs. 37 crore during 2013-14 to Rs. 45 crore during 2014-15 and was further increased to Rs. 60 crore in 2015-16. During the financial year 2016-17, an amount of Rs. 65 crore has been proposed for the Backward Area Sub Plan. Sh. Prem Kumar Dhumal, Sh. Rajiv Saizal, Sh. Rikhi Ram Kondal, Sh. Krishan Lal and Sh. Suresh Bhardwaj raised the issue that what actions are been taken to tackle jaundice and to prevent its recurrence?

18.03.2016/1320/RKS/DC/2

Mr. Speaker Sir, it is fact that some part of Shimla was effected by jaundice, it is a matter of regret and also shows negligence by some agencies. But it cannot be made to show as if the entire water supply system has graft in the State. I think this issue has been grown out of context and given dimensions which are not there. Speaker Sir, it is a matter of great concern that jaundice spread in Shimla and Solan town. The State Govt. has taken immediate effective steps to control it. The supply from the Ashwani Khud was immediately discontinued, from where the jaundice had its origin. The IPH Deptt. has taken various steps to improve the working of STP Malyana. The State Govt. has provided additional Rs. 14 crore for improving the water supply and sewerage treatment in Shimla town. A standard operating procedure for inspection and testing of sewerage treatment and water treatment plants has been put in place.

Continued by DC….

18.03.2016/1325/SLS/DC/1

Chief Minister continues…….

The State Govt. has also provided additional Rs. 30 crore for water treatment plants in 2016-17. I have also proposed various measures in para-64 of my Budget Speech to ensure providing safe and adequate drinking water to the people of Himachal Pradesh. **I assure this House that the State Govt. will continuously take effective steps to ensure that such recurrence of disease does not happen in future.**

Dr. Rajeev Kumar Bindal and Sh Mahender Singh raised the issue that the State is selling power at the rate of Rs. 2.25 per unit, whereas the State can sale at much better price. Speaker Sir, the State Govt. in last three years have sold 7,401 million unit of electricity at an average rate of Rs.3.25 per unit and have earned a revenue of Rs.2403 crore.

The Hon'ble Members have raised the issue of differential rate at the time of sale of power. Here, I would like to point out that the rate of power fluctuates depending upon the period of the day as well as the month of the year, in which power is being sold. In last few years, there has been a total shift in the market conditions and market has become a buyer's market in place of seller's market, as it was in past. Now, various Electricity Boards of the States float tenders and buy power from the lowest bidder. These States demand firm power for specific days. The State Govt. has been participating in various tenders and getting a price ranging from Rs. 3 to Rs. 5. However, many a time the State Govt. is left with the unsold power. In that situation, the State is left with no alternative but to sell the remaining power on the power exchange to avoid losses. The power exchange is a trading platform like the Bombay Stock Exchange, where the rate of power is determined based on supply and

demand of power on a particular day and time. Hence, the State Govt. is making all out efforts to get best price for power.

18.03.2016/1325/SLS/DC/2

Dr. Rajeev Kumar Bindal has stated that the State Government is taking no steps for the value addition of farm products. Speaker Sir, I would like to inform this August House that the UPA Government had started a National Mission on Food Processing to promote industries which add value to the farm products. However, the Government of India has stopped funding the National Mission on food processing since March, 2015. Considering the importance of value addition to farm products, my Government has decided to start the State mission of Food Processing. I have provided Rs.10 crore for this mission in 2016-17.

Continued by AG…

18032016/1330/RG-AG/1

Chief Minister Continues . . .

Shri Mahender Singh and Shri Maheshwar Singh raised the issue that under Demand No. 32, a lump sum provision for Hand Pumps, Sewerage, NABARD, CRF and PMGSY schemes have been made for 2016-17; whereas the funds should be allocated zonewise to check discrimination.

The lump sum provisions under the above mentioned schemes in the Demand No. 32 are made from the year and a separate Demand for Grants for Scheduled Caste Component Plan was introduced. Out of these lump sum provisions, further allocations are made on the basis of an objective criteria

based on the proportion of SC population as per the guidelines for implementation of Scheduled Caste Component Plan.

Speaker, Sir, Prof. Prem Kumar Dhumal, Smt. Sarveen Chaudhary, Shri Gulab Singh Thakur, Shri Ravinder Singh and Shri Suresh Bhardwaj raised the issue that the new schemes announced are replication of the central schemes or central schemes have been renamed as State schemes. Moreover, the budget proposals for 2016-17 are repetition of 2012-13.

Speaker Sir, I have announced many new schemes during my Budget Speech for the year 2016-17 which are:-

- Mukhya Mantri Khet Sanrakashan Yojna.
- Panchayat Pashu Dhan Puraskar Yojana,
- Mukhya Mantri Aawas Yojana,
- Lal Bahadur Shashtri Kaamgar Evam Shashtri Aajeevika Yojana,
- Chief Minister Start-up Scheme,
- Mukhya Mantri Sadak Yojana,
- Mukhya Mantri Shikshak Samaan Yojana,
- Mukhya Mantri Adarsh Vidyalaya Yojana,
- Mukhya Mantri Gyandeep Yojana,

.

18032016/1330/RG-AG/2

- Himachal Pradesh Patarkaar Kalyan Yojana,
- Himachal Universal Health Protection Scheme,
- State Mission on Food Processing.
- Panchayat Balika Gaurav Puraskar
- Mukhya Mantri Vardi Yojana.

Speaker Sir, all these schemes are State Schemes, being fully funded by the State Government. We have not changed the name of any Central Scheme to fund these schemes. The budget for Central Schemes like, PMGSY, Indira Aawas Yojna, RSBY etc. have been separately kept in the budget documents.

Contd. By AG in English . . .

18032016/1335/MS-AG/1

Chief Minister Continues . .

Speaker Sir, few members have raised the issue that the budget 2016-17 is copy of 2012-13 budget of BJP Government. They want to take credit that it was their time. We don't copy anybody especially I will be the last person to copy BJP. In fact they have been copying our schemes and changing their names. I would like to ask them, whether any of the schemes mentioned above figured in 2012-13? Let them prove it. Let them mention even one scheme which we have copied from them. Therefore, they know our Budget is very good. So, instead of giving us the due credit कहते हैं कि हमारे बजट को कॉपी किया है। We don't copy in any matter. Let me assure you. These schemes and many other public welfare measures announced in the present budget have been welcomed by the people of the State. The Members from the Opposition Benches have raised this issue just to divert the attention of the people.

Prof. Prem Kumar Dhumal, Smt. Sarveen Chaudhary, Shri Gulab Singh Thakur, Shri Jai Ram Thakur, Shri Rikhi Ram Kaundal, Shri Rajiv Saizal, Shri Inder Singh and Shri Vinod Kumar raised the issue that the budget is jugglery of figures, disappointing, anti youth, anti farmers and no new initiatives have been taken.

Speaker, Sir, I am unable to understand as to why Opposition has failed to see the new policies and initiatives in the budget. If one goes through my Speech with open mind, the budget 2016-17 has provided relief to all the sections of the society. The budget has also fixed sustainable development goals to be achieved by 2022. This budget provides a clear cut fiscal direction for investments in critical sectors such as Agriculture, Horticulture, Education, Health, Irrigation, Industries and Power Sector.

Speaker Sir, I would like to apprise the Hon'ble Members of this August House that the budget for the department of Horticulture has been raised

18032016/1335/MS-AG/2

from Rs. 154 crore in 2012 -13 to Rs. 286 crore in 2016-17. Similarly the budget of the Agriculture Department has been raised from Rs. 358 crore to Rs. 482 crore for the benefit of the farmers.

Speaker Sir, farmers are facing weather and market price fluctuations and risk of damage by wild animals and monkeys. Therefore, we have extended the Weather Based Crop Insurance Scheme for all areas and all crops in the State and propose to launch a New Scheme i.e. "Mukhya Mantri Khet Sanrakshan Yojna" to ensure protection of farms from wild animals and monkeys. We are providing adequate budget for promoting off-season vegetables, construction of Poly Houses, Micro-Irrigation, purchase of Power Sprayers, Power Tillers etc. I have proposed a budget of Rs. 643 crore for Irrigation and development of Command Areas. Further, Himachal Pradesh Horticulture Development Project with an investment of Rs. 1115 crore will be launched in 2016-17 for the benefit of Horticulturists of the State.

The problem of abandoned cattle has increased manifold in rural areas. With a view to contain this problem, we propose to launch a new scheme "Panchayat Pashudhan Purskar Yojna".

Contd. By DC in English . . .

18.03.2016/1340/JS/AS/1

Chief minister continues…..

We propose to increase milk purchase price to Rs. 21.80 per litre in 2016-17 which was Rs. 18.80 per litre in 2013-14. We have introduced a new scheme "Mukhya Mantri Aawas Yojna" to provide housing subsidy for BPL families of general categories and budget has been earmarked to construct 12 thousand houses under various housing schemes

New Scheme "Lal Bahadur Kamgar Evam Shahri Ajeevika Yojna" has been launched in all merged wards of Municipal Corporation and newly created Nagar Panchayats to provide basic civic amenities and livelihood.

The budget also amply indicates our approach towards promotion of Industries in the State. Various concessions on electricity duty, VAT, Stamp duty and fees have been extended to the entrepreneurs.

A new scheme "Chief Minister Start Up /New Industries Scheme" has been launched. It includes 4 percent interest subvention upto a loan of Rs. 10 lakh.

A new scheme "Mukhya Mantri Sadak Yojna" has been launched to provide last mile connectivity to villages/habitations. This budget lays emphasis on improving quality of education. A new scheme "Mukhya Mantri Shikshak Samman Yojna" has been launched.

A new scheme "Mukhya Mantri Aadarsh Vidyalaya Yojna" has been launched to provide State of Art Infrastructure and teaching facilities in two Senior Secondary Schools in each constituency.

A new scheme "Mukhya Mantri Gyandeep Yojna" launched to provide interest subvention of 4 percent to all Himachali students availing Education loan upto Rs. 10 lakh.

18.03.2016/1340/JS/AS/2

A new scheme "Mukhya Mantri Vardi Yojna" launched to provide uniform to students of +1 and +2 classes.

A new scheme "Balika Gaurav Purskar Yojna" has been launched to reward the Panchayats where there will be best female birth rate relative to male birth rate.

On the Health front, we have proposed a new scheme "Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme" for the benefit of all persons in the State. The Government is committed to uplift the unprivileged, weaker and vulnerable sections of the society. The most vulnerable section of the Society like BPL Families, Ekal Naris, Widows with children, senior Citizens and physically or mentally disabled, all have been at the centre stage of the budget 2016-17.

We have increased social security pension from Rs. 600 to Rs. 650 per month. The monthly pension of young widows with less than 45 years with child/children raised from Rs. 600 to Rs. 1,200 per month. Marriage grant of residents of Nari Sewa Sadans raised from Rs. 25 thousand to Rs. 51 thousand. Pension to persons with 70 percent disability and persons aged 80 years and above increased from Rs. 1,100 to Rs. 1,200 per month.

Continued by AS…

18.03.2016/1345/SS-AS/1

Chief Minister continues…..

The budget proposal for the year 2016-17 have ensured safety, security, dignity and equality to women. Various new incentive schemes have been proposed in this budget to reverse the adverse trend in sex ratio in the State. The cash grant for providing credible information about illegal foeticide raised from Rs. 10 thousand to Rs. 1 lakh. We feel that it is very important that the residential house should be in the name of women. Therefore, Stamp Duty for registration of any house will be only 3 percent compared to 6 percent being charged in case of men.

The Government employees are at the heart of administration and their welfare has a direct bearing on the quality of governance. The budget proposals have ensured benefits to all the employees i.e daily wager, contract and regular etc.

This budget is welfare, development and growth oriented budget and will accelerate the process of building the State on sound lines. I fail to understand how this budget can be termed as disappointing, directionless and devoid of any new policy. They are old slogans. As I have said, I have presented so many Budgets in the State and the Opposition in every budget, I have presented, has used these phrases disappointing, directionless and devoid of any new policy. If I start mentioning all the achievements made and the new announcements made now, it will take more time than my Budget Speech.

Speaker Sir, I have tried to cover most of the issues raised by the Hon'ble Members in my reply. I also appreciate the Hon'ble Members from the Ruling Party who have participated in this Budget discussion and who have not only

supported the Budget but also given concrete suggestions. I have taken note of them and I will see many of them which are feasible, will be implemented.

18.03.2016/1345/SS-AS/2

Some points might have been left out, but no Member should doubt our grit and determination of work for all round development of State. In a democratic set up, there is a big room for discussion and debate. However, criticism should be objective and not merely for the sake of criticism. We are working in a right direction and no obstacle can come in our way to deter us from the path of inclusive development of the State.

May I conclude by saying:-

"हरेक राह में चिराग जलाना है मेरा काम,
हरेक राह में चिराग जलाना है मेरा काम,
तेवर हवाओं के मैं देखा नहीं करता।"

'जय हिन्द, जय हिमाचल'।

Continued by DC……

18.03.2016/1350/केएस/डीसी/1

Speaker: So, before I proceed further, I would like to say that the points raised by the Members of the Opposition in between the reply of the Hon'ble Chief Minister were uncalled. As the points raised had already been discussed and debated during the General Budget, there was no need and there is no point in raising the same during the reply of the Government.

इससे पूर्व कि मैं आज की सभा की बैठक स्थगित करूं, सदन की विभागीय स्थाई समितियों से यह अपेक्षा है कि वे सत्र के स्थगन के दौरान अनुदान मांगों का बारीकी से अध्ययन करें और उसके बाद अपने-अपने प्रतिवेदन 28 मार्च, 2016 को जब सभा की बैठक पुनः आरम्भ होगी, प्रस्तुत करेंगें। मुझे पूर्ण आशा है कि समितियों के सभापति एवं सभी सदस्य गहन रुचि लेकर इस कार्य को सम्पन्न करेंगें और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां सरकार को सौंपेंगें। अन्त में, मैं इस सदन की ओर से प्रदेशवासियों को होली की मुबारकवाद देता हूं।

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, 28 मार्च, 2016 के 2.00 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 18.03.2016 **सचिव।**